रायपुर, जबलपुर, कटनी, भोपाल, मंडला, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, नरसिंहपुर, सिवनी से एक साथ प्रकाशित

yashbharat.co.in

नये जमाने के साथ..

यश भारत

● वर्ष-1 अंक-167 ● रायपुर ● शुक्रवार ,6 नवम्बर , 2026 ● मूल्य- 4 रुपए ● पृष्ठ-8 ●कार्तिक कृष्ण पक्ष 12 ● विक्रम संवत् 2083

हंसकर काम करो ताकि मन हल्का रहे। तनाव के साथ काम आगे नहीं बढ़ता।

यूजर्स की पोस्ट के लिए सोशल मीडिया कंपनियां भी होंगी जिम्मेदार, सरकार सेफ हार्बर सुरक्षा खत्म करने की तैयारी में

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स (X) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कानूनी जवाबदेही बढ़ाने की तैयारी कर रही है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों में बदलाव कर इन कंपनियों को मिलने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा खत्म करने पर विचार कर रही है। ऐसा होने पर यूजर्स की ओर से पोस्ट किए गए कंटेंट, वीडियो और कमेंट के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को भी कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा। अभी तक इन प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स की सामग्री के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं माना जाता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इस संबंध में सोशल मीडिया नियमों में संभावित बदलावों पर चर्चा शुरू कर दी है। प्रस्ताव के तहत आईटी एक्ट की धारा 79 के अंतर्गत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा के दायरे को सीमित किया जा सकता है। सरकार इस सुरक्षा को सोशल मीडिया कंपनियों से हटाकर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, टेलीकॉम और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स तक सीमित करने पर विचार कर रही है। वर्तमान व्यवस्था में आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को सेफ हार्बर का संरक्षण मिलता है। इसका मतलब है कि किसी यूजर की ओर से पोस्ट की गई सामग्री के लिए प्लेटफॉर्म को सामान्यतः जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, बशर्ते वह कानून के तहत निर्धारित शर्तों और उचित सावधानियों का पालन करे। इसी व्यवस्था के चलते मेटा, गूगल और एक्स जैसी कंपनियां यूजर जनरेटेड कंटेंट के आधार पर बड़े कारोबारी साम्राज्य खड़े कर सकी हैं।सरकार के एक वर्ग का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब केवल सूचनाओं के आदान-प्रदान का माध्यम नहीं रह गए हैं।



महादेव सट्टा ऐप का को-प्रमोटर रवि उप्पल यूएई में गिरफ्तार, अब भारत लाने की तैयारी तेज

रायपुर, यशभारत। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ चल रही जांच में भारतीय एजेंसियों को एक और बड़ी सफलता मिलने की खबर है। ऐप के को-प्रमोटर रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई है। भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर इंटरपोल की ओर से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर यूएई के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। हालांकि, भारतीय एजेंसियों को गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं मिली है। अब अधिकारी गिरफ्तारी की पुष्टि कराने और रवि उप्पल को भारत लाने के लिए प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुटे हैं। यह घटनाक्रम महादेव ऐप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के महज तीन दिन बाद सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष टीम सौरभ चंद्राकर को एक नवंबर को भारत लेकर पहुंची थी। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच चल रही है। अब रवि उप्पल की गिरफ्तारी की खबर से इस पूरे नेटवर्क की जांच में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।



हवाला नेटवर्क और नेताओं-अफसरों से संपर्क की जिम्मेदारी -जांच एजेंसियों के मुताबिक, रवि उप्पल महादेव सट्टा ऐप के नेटवर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आरोप है कि वह करोड़ों रुपए के हवाला लेनदेन को संभालता था। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नेताओं और अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उसके पास थी। अधिकारियों के मुताबिक, रवि उप्पल की उम्र करीब 46 वर्ष है। उसे वर्ष 2023 में भी यूएई के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसके बाद उसके प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश वानुअतु जाने और वहां की नागरिकता हासिल करने की जानकारी सामने आई थी। ईडी के मुताबिक, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों ने वानुअतु की नागरिकता प्राप्त की थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि विदेशी नागरिकता और अलग-अलग देशों में ठिकाने बदलने की कोशिशों के जरिए दोनों गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे थे। नवंबर 2025 में ईडी को जानकारी मिली थी कि रवि उप्पल यूएई में उपलब्ध नहीं है और उसका पता नहीं चल पा रहा है। इसके बाद जनवरी 2026 में उसने इंटरपोल के कमीशन फॉर द कंट्रोल ऑफ फाइल्स (सीसीएफ) में अपील कर अपना रेड कॉर्नर नोटिस हटाने की मांग की थी। ईडी ने उसकी इस मांग का विरोध किया और उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वांटेड आरोपी तथा फरार बताया था।

रोनाल्डो का इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास



लिस्बन, एजेंसी।क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 41 साल की उम्र में उनके इस फैसले के साथ ही पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए उनका 23 साल लंबा शानदार सफर समाप्त हो जाएगा। रोनाल्डो ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नवंबर के अंतरराष्ट्रीय ब्रेक के बाद वह पुर्तगाल की प्रतिष्ठित नंबर-7 जर्सी टीम को लौटा देंगे। उनके संन्यास के साथ अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के एक ऐसे अध्याय का अंत होगा, जिसमें उन्होंने गोल, रिकॉर्ड और उपलब्धियों के मामले में पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। रोनाल्डो ने 20 अगस्त 2003 को कजाकिस्तान के खिलाफ पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम से अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। उस समय उनकी उम्र महज 18 साल थी। शुरुआती दौर में अपनी रफ्तार, शानदार ड्रिब्लिंग और गोल करने की क्षमता से पहचान बनाने वाले रोनाल्डो ने धीरे-धीरे खुद को दुनिया के सबसे प्रभावशाली फुटबॉल खिलाड़ियों में स्थापित कर लिया। 23 वर्षों के दौरान उन्होंने पुर्तगाल के लिए 234 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और 146 गोल दागे।

अंतरराष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। इसके अलावा उन्होंने 46 गोल में असिस्ट देकर अपने साथियों को गोल करने में मदद की।

भाजपा-कांग्रेस समेत 68 दलों के संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से गायब, नौ महीने बाद भी नहीं हुआ अपडेट



नई दिल्ली, यशभारत। राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता लाने और उनके संगठनात्मक ढांचे की जानकारी सार्वजनिक करने के चुनाव आयोग के निर्देशों का देश की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां पालन नहीं कर रही हैं। आयोग के आदेश के नौ महीने बाद भी भाजपा, कांग्रेस समेत 68 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के नए संविधान और संशोधित नियम सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सके हैं। देश के कुल 73 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से केवल पांच ने ही आयोग के निर्देश के बाद अपने संविधान और संगठनात्मक नियमों की जानकारी अपडेट कराई है।

चुनाव आयोग ने 8 दिसंबर 2025 को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अपने संविधान में किए गए संशोधनों और संगठनात्मक नियमों की अद्यतन जानकारी आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों की आंतरिक कार्यप्रणाली, संगठनात्मक चुनाव और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। इसके बावजूद अधिकांश दलों ने अब तक इस दिशा में जरूरी कार्रवाई नहीं की है। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक, निर्देश के बाद जिन पांच दलों ने अपने दस्तावेज अपडेट कराए हैं, उनमें एआईएमआईएम, बीजू जनता दल, रिवोल्यूशनरी गोअन्स पार्टी, वॉयस ऑफ द पीपल पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी शामिल हैं। इसके उलट देश के छह राष्ट्रीय दलों में से किसी ने भी निर्देश के बाद अपने संविधान को नई तारीख के साथ सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराया है। इन राष्ट्रीय दलों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल हैं। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संविधान पर जुलाई 2022 और शिवसेना के संगठनात्मक दस्तावेज पर मई 2022 की तारीख दर्ज है। इससे राजनीतिक दलों के संगठनात्मक दस्तावेजों को नियमित रूप से अपडेट करने की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित

कांग्रेस की 100 से ज्यादा खामियों की आपत्तियां खारिज हेमंत कटारे बोले- हाईकोर्ट में चुनौती देंगे

भोपाल, यशभारत। मध्यप्रदेश से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो गए हैं। उनके निर्वाचन के साथ ही प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटों का राजनीतिक समीकरण भी बदल गया है। अब मध्यप्रदेश से राज्यसभा में भाजपा के 10 और कांग्रेस का एक सदस्य रहेगा। इससे पहले भाजपा के नौ और कांग्रेस के दो सदस्य थे। पुरी के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा के साथ ही भाजपा ने प्रदेश में राज्यसभा की एक और सीट पर कब्जा जमा लिया है।पुरी के नामांकन को लेकर कांग्रेस ने शुरुआत से ही सवाल खड़े किए थे। पार्टी ने उनके नामांकन और शपथपत्र में 100 से अधिक कमियां होने का दावा करते हुए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराई थीं। कांग्रेस ने विशेष रूप से शपथपत्र में पत्नी के नाम का उल्लेख नहीं होने, विदेशों में स्थित संपत्तियों का विवरण अमेरिकी डॉलर और स्विस फ्रैंक में दिए जाने तथा जेनेवा स्थित संपत्ति और विदेशी बैंक खातों की जानकारी को लेकर सवाल उठाए थे। इसके अलावा नोटरी सत्यापन और शपथपत्र प्रमाणित करने की प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई गई थी। हालांकि, रिटर्निंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा ने सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए पुरी के नामांकन को वैध माना। इसके बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया।कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को स्वीकार करने के बजाय अब इसे हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही चुनाव याचिका दायर की जा सकती है।



चार करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप, अनवर ढेबर-कुबेर राठी समेत छह पर एफआईआर



रायपुर यशभारत। रायपुर में जमीन के पुराने सौदे को लेकर कारोबारी से चार करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। कारोबारी बलिराम धरमानी (62) की शिकायत पर पुलिस ने अनवर ढेबर, कुबेर राठी समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि जमीन की रजिस्ट्री को लेकर रकम देने का दबाव बनाया गया और इनकार करने पर कारोबारी के साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। मामले में संदीप अग्रवाल, आसिफ मेमन, नागेंद्र कुमार और विवेक जोशी उर्फ मोंटी जोशी के नाम भी शामिल हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, कालीबाड़ी निवासी बलिराम धरमानी ने वर्ष 2018 में बोरड परिवार की लाभांडी स्थित करीब 2.60 लाख वर्गफीट जमीन का सौदा किया था। इसमें से 40 हजार वर्गफीट जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम हो गई थी, जबकि शेष जमीन के लिए एग्रीमेंट किया गया था। बताया गया कि परिवार के सदस्यों के बीच विवाद होने के कारण बाकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2022 में संदीप अग्रवाल कटोरा तालाब स्थित बलिराम के कार्यालय पहुंचे और विवादित जमीन की रजिस्ट्री कराने के बदले चार करोड़ रुपए की मांग की।

बलिराम धरमानी के मुताबिक, बाद में उन्होंने अपने नाम की 40 हजार वर्गफीट जमीन बोरड परिवार को वापस कर दी थी। इसके बदले उन्हें 3.15 करोड़ रुपए मिले थे। उनका दावा है कि इस लेनदेन के बाद बोरड परिवार के साथ कोई आर्थिक हिसाब बाकी नहीं था। इसके बावजूद चार करोड़ रुपए की मांग की जाती रही। शिकायत के अनुसार, 26 सितंबर 2026 को रहमानिया चौक स्थित बबू प्लाजा में इस मामले को लेकर बैठक हुई थी। यहां फिर चार करोड़ रुपए की मांग किए जाने का आरोप है।

इसके अगले दिन 27 सितंबर को फाफाडीह स्थित होटल वेलिंगटन में दोबारा बैठक हुई। बलिराम का आरोप है कि उन्होंने रकम देने से इनकार किया तो अनवर ढेबर और कुबेर राठी ने उनके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। अन्य आरोपियों पर भी धमकाने में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात कही है।पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 308(2), 351(3), 296, 115(2), 61(2) और 3(5) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। गंज पुलिस ने एफआईआर को संवेदनशील श्रेणी में रखा है, जिसके चलते इसकी ऑनलाइन उपलब्धता सीमित की गई है।

दिल्ली में निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत ढही, दो की मौत, 4 घायल

मलबे में 15 लोगों के दबे होने की आशंका



नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास गली सत्तारा में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक भरभराकर ढह गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए हैं। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, मलबे में करीब 15 लोगों के दबे होने की आशंका है। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दमकल, पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य बचाव दलों ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, हादसा सुबह करीब 9:50 बजे हुआ। सूचना मिलते ही दमकल की छह गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं। इमारत के आसपास की गलियों में रास्ता काफी संकरा होने के कारण बचाव अभियान में परेशानी आ रही है। इसके बावजूद बचाव दल मलबे को हटाकर उसमें फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। घटनास्थल को पुलिस ने घेराबंदी कर सील कर दिया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इमारत में पिछले कुछ समय से निर्माण कार्य चल रहा था। करीब 15 दिन पहले निर्माण कार्य रोक दिया गया था। हादसे के वक्त मजदूर छत के नीचे लगाए गए सपोर्ट सिस्टम को हटा रहे थे। इसी दौरान पूरी इमारत अचानक ढह गई। एमसीडी के एक अधिकारी के मुताबिक, निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप नहीं थी और उसे ठीक से सेट भी नहीं किया गया था। प्रारंभिक तौर पर इसे हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि, वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा।

जंतर-मंतर हिंसा मामले में शिकायतों का टोटा, जांच कमेटी अब तक बेनतीजा

प्रदर्शनकारियों और पुलिस पर हमले के पर्याप्त सबूत नहीं-सुको

नई दिल्ली, यशभारत। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा और पुलिस की ज्यादती के मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि घटना की जांच के लिए गठित हाई पावर्ड कमेटी को अब तक बेहद कम शिकायतें मिली हैं। पर्याप्त शिकायतें और साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण कमेटी फिलहाल किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पीड़ितों की ओर से पहले से दाखिल वीडियो, याचिकाएं और हलफनामे जांच कमेटी को सौंपने की अनुमति देते हुए संबंधित पक्षों से जवाब लेकर नियमित अंतराल पर अंतरिम रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में गठित हाई पावर्ड इन्क्वायरी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शिकायतें आमंत्रित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल और अन्य माध्यमों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम लोगों



ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। 29 अक्टूबर को हुई कमेटी की बैठक में महज एक शिकायतकर्ता हलफनामे के साथ उपस्थित हुआ था। कमेटी के मुताबिक, शिकायतों की संख्या और उपलब्ध सामग्री इतनी कम है कि घटना के संबंध में अभी कोई अंतिम राय बनाना संभव नहीं है। कमेटी ने बताया कि शिकायतें प्राप्त करने के लिए 13 अक्टूबर को ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया था। इस पर शिकायत दर्ज कराने के लिए नाम, आधार नंबर या अन्य पहचान संबंधी जानकारी देना अनिवार्य नहीं रखा गया था। पोर्टल तक पहुंच केवल कमेटी के चेयरमैन और संबंधित अधिकृत लोगों को दी गई है। इसके अलावा देशभर के 149 अखबारों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कर पीड़ितों और प्रत्यक्षदर्शियों से शिकायतें आमंत्रित की गई थीं। ईमेल, डाक और कमेटी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से शिकायत देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी। 17 अक्टूबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और 21 अक्टूबर को दोबारा शिकायतें मांगी गईं, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद अपेक्षित शिकायतें नहीं मिलीं। कमेटी को ईमेल, डाक या कार्यालय में सीधे तौर पर भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उन्होंने पोर्टल शुरू होने से पहले ही कमेटी को शिकायतें सौंप दी थीं। पोर्टल शुरू होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत एक और शिकायत भी जमा कराई गई थी। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से दाखिल वीडियो और अन्य दस्तावेज कमेटी को उपलब्ध करा दिए जाएं, ताकि प्रत्येक पीड़ित को अलग-अलग उपस्थित होकर अपनी बात रखने की जरूरत न पड़े।

हिरासत में लेते ही शुरू होगी 24 घंटे की समय सीमा

गिरफ्तारी दर्ज करने में देरी का नहीं मिलेगा फायदा

नई दिल्ली। यशभारत। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक समयसीमा को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि 24 घंटे की अवधि की गणना व्यक्ति को वास्तविक रूप से हिरासत में लेने के समय से शुरू होगी, न कि पुलिस या जांच एजेंसी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज किए जाने के समय से। इसका मतलब है कि जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति को पहले हिरासत में रखकर बाद में उसकी गिरफ्तारी दिखाकर कानूनी समयसीमा को आगे नहीं बढ़ा सकतीं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत और औपचारिक गिरफ्तारी के बीच के अंतर का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता। यदि जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से अपने नियंत्रण में ले लेती है, तो उसी समय से 24 घंटे की गणना शुरू हो जाएगी। इस अवधि में संबंधित व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन होने पर हिरासत की वैधता को चुनौती दी जा सकती है और व्यक्ति को रिहा करने का अधिकार बन सकता है।यह महत्वपूर्ण फैसला त्रिपुरा के चार लोगों की याचिका पर आया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उन्हें हिरासत में लेने और उनकी औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज करने के बीच करीब 21 घंटे का अंतर रखा गया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने 24 घंटे की संवैधानिक समयसीमा की व्याख्या स्पष्ट की।

तमिलनाडु-केरल में ईडी की 11 जगह छापेमारी, को-ऑपरेटिव सोसायटी में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप

नई दिल्ली ईएमएस। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु और केरल में 11 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई भारत लजना मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी और उसके प्रमोटर आर. प्रेमकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई। ईडी की कोच्चि यूनिट ने पीएमएलए के तहत यह कार्रवाई की। प्रेमकुमार सोसायटी के संस्थापक सदस्य होने के साथ वास्तविक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। आरोप है कि उन्होंने सोसायटी में लोगों द्वारा जमा कराई गई करोड़ों रुपये की रकम अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराई। जांच एजेंसी का यह भी आरोप है कि सोसायटी का रागम थिएटर गिरवी रखकर प्राप्त रकम संस्था के खाते में जमा नहीं कराई गई। इसके अलावा कांचीपुरम में करीब 500 एकड़ जमीन पत्नी के नाम पर खरीदने का आरोप भी है।

ट्रंप की चुनावी हार पर ईरान में जश्न, तेहरान में अमेरिकी और इस्राइली नेताओं के पोस्टर जलाए

***तेहरान, एजेंसी।** अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को लगे बड़े झटके का असर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। चुनावी नतीजों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार समर्थकों और कट्टरपंथी समूहों ने जश्न मनाते हुए अमेरिका और इस्राइल के शीर्ष नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के कमजोर प्रदर्शन को लेकर उत्साह भी दिखाई दिया।*



ईरान में इन प्रदर्शनों को ट्रंप प्रशासन की नीतियों और दोनों देशों के बीच जारी तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चुनावी नतीजों को ट्रंप की राजनीतिक मुश्किलों से जोड़कर पेश किया। ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य तनाव तथा इस्राइल के साथ अमेरिका की नजदीकी लंबे समय से तेहरान की राजनीति में विरोध का प्रमुख मुद्दा रही है।

महंगाई और ईरान युद्ध ने बढ़ाई ट्रंप की मुश्किलें

अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को हुए नुकसान के पीछे घरेलू अर्थव्यवस्था और विदेश नीति से जुड़े मुद्दों को अहम माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की महंगाई और ईरान के साथ सैन्य टकराव मतदाताओं के बीच चर्चा के प्रमुख विषय रहे। डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन मुद्दों को उठाकर ट्रंप प्रशासन को घेरा।

माना जा रहा है कि महंगाई और युद्ध से पैदा हुई आर्थिक अनिश्चितता ने रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में भूमिका निभाई। ईरान से जुड़े संघर्ष को लेकर अमेरिकी नागरिकों की चिंता भी ट्रंप प्रशासन के लिए चुनौती बनी। युद्ध के आर्थिक प्रभावों और विदेश नीति को लेकर उठे सवालों ने चुनावी बहस को प्रभावित किया। नतीजों के बाद ईरान में हुए प्रदर्शनों को इसी राजनीतिक घटनाक्रम की अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है।

चुनावी झटके के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के अपने फैसले का बचाव किया है।

उन्होंने स्वीकार किया कि ईरान युद्ध के कारण पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिससे अमेरिकी नागरिकों पर महंगाई का दबाव बढ़ा। हालांकि, उनका कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना जरूरी था।

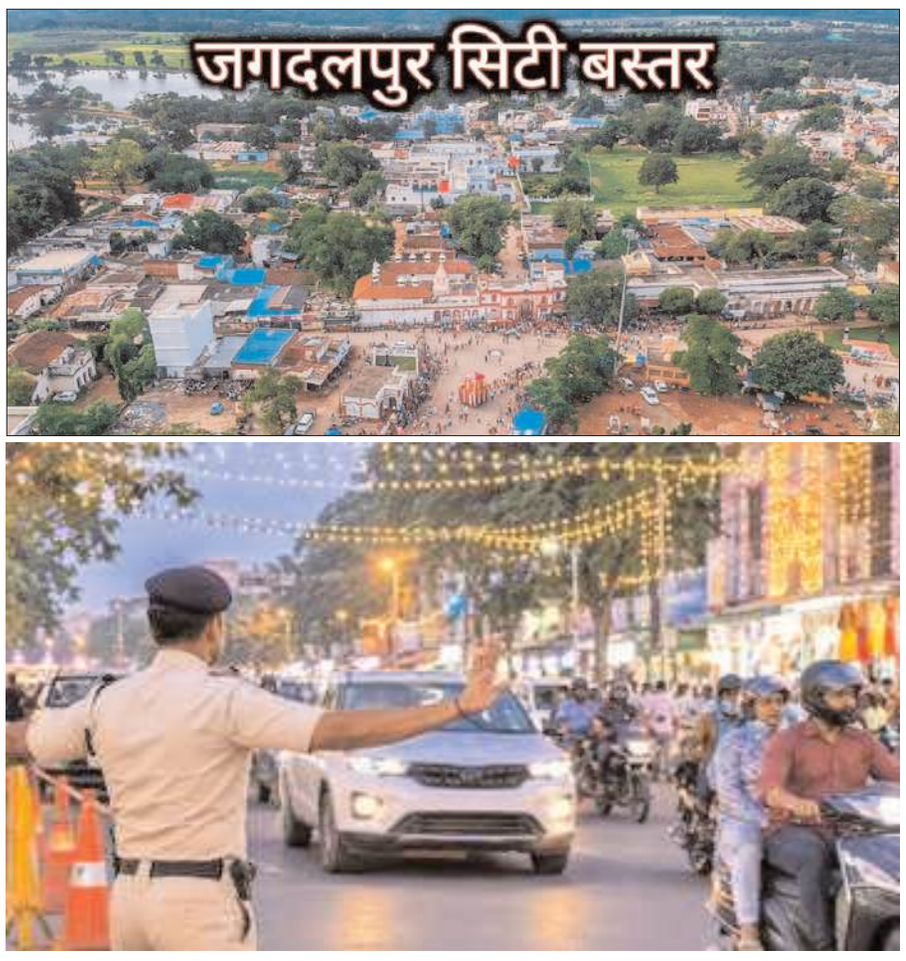
ट्रम्प ने माना- ईरान जंग के कारण मिडटर्म हार

मौका मिला तो फिर करेंगे हमला



वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने स्वीकार किया है कि ईरान के साथ युद्ध का असर मिडटर्म चुनाव में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ा और उसे बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। चुनाव में पार्टी दोनों सदनों में अपना बहुमत गंवा चुकी है। इसके बावजूद ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सही ठहराते हुए साफ कहा कि अगर उन्हें दोबारा फैसला लेने का मौका मिला तो वह फिर हमला करेंगे। उनका कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई करना जरूरी था और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रम्प ने माना कि ईरान के साथ युद्ध के चलते कुछ समय के लिए अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। इसका असर आम अमेरिकी नागरिकों पर पड़ा और चुनाव में मतदाताओं की नाराजगी भी सामने आई। हालांकि, ट्रम्प ने इस आर्थिक दबाव को सैन्य कार्रवाई रोकने की वजह मानने से इनकार कर दिया।

धनतेरस और दीपावली पर जगदलपुर में सुगम आवागमन के लिए व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी



भारी वाहनों पर पाबंदी के साथ तय हुए पार्किंग स्थल

जगदलपुर। धनतेरस और दीपावली के पावन पर्व पर शहर के प्रमुख बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने तथा सुगम आवागमन बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस बस्तर ने एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। 06 से 08 नवंबर 2026 तक लागू रहने वाली इस व्यवस्था के तहत शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए विशेष पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं।

अनुपमा चौक, आकांक्षा होटल रोड, अग्रसेन चौक, संजय मार्केट और मिताली चौक की ओर से आने वाले वाहनों के लिए चावल लाईन रोड में पार्किंग तय की गई है, जबकि चांदनी चौक, न्यू नरेन्द्र टॉकिज, गोल बाजार, एम.एल.बी. स्कूल और संजय मार्केट की गाड़ियों को हाथा ग्राउंड तथा जिला शिक्षा कार्यालय के सामने स्थित बस्तर हाई स्कूल ग्राउंड में पार्क कराया जाएगा। इसी प्रकार अनुपमा चौक, अग्रसेन चौक और गुरु गोविंद सिंह चौक के वाहनों के लिए विवेकानंद स्कूल मैदान, एस.बी.आई. चौक, बस्तर क्लब और बली राम चौक से आने वाले वाहनों हेतु कोतवाली चौक नगर निगम अंडरग्राउंड पार्किंग व जेल रोड, तथा दुर्गा चौक व बलीराम चौक के वाहनों के लिए ठाकुर रोड स्थित सुधीर जैन का बाड़ा निर्धारित किया गया है।

स्टेट बैंक चौक और चांदनी चौक के वाहनों को प्रतापदेव वार्ड में कन्हैया बीकानेर के पास खाली मैदान में जगह दी जाएगी, वहीं लालबाग मैदान में लगने वाली पटाखा दुकानों पर आने वाले ग्राहकों के लिए मैदान के किनारे ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

दीपावली पर्व के दौरान अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए संजय मार्केट से मिताली चौक, मिताली चौक से दंतेश्वरी मंदिर और मिताली चौक से गोल बाजार मार्ग पर आवश्यकतानुसार दोपहिया व चारपहिया वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित रखा जाएगा। ऐसी स्थिति में यातायात को सुचारू रखने के लिए वाहनों को अग्रसेन चौक, न्यू नरेन्द्र टॉकिज रोड, मिताली चौक से मेन पोस्ट ऑफिस रोड, बली राम चौक से दलपत सागर तथा गोल बाजार चौक से एम.एल.बी. स्कूल की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही, 06 से 08 नवंबर तक प्रतिदिन प्रातः 07:00 बजे से लेकर रात्रि 24:00 बजे तक शहर में भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश व निकास पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान जगदलपुर से सुकमा और दंतेवाड़ा जाने वाले भारी वाहनों को आड़ावाल-तेलीमारेंगा बाईपास रोड से होकर गुजरना पड़ेगा, हालांकि यात्री बसों को उनके निर्धारित मार्गों पर चलने की अनुमति रहेगी और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस रोक से पूरी तरह छूट दी गई है।

पर्व के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छोटे व्यापारी अक्सर सड़क किनारे फल, फूल और पूजन सामग्री की अस्थाई दुकानें लगाते हैं। इस स्थिति में यातायात व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे लेकर यातायात पुलिस बस्तर ने स्थानीय व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों को चिन्हित व निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें, जिससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह सुगम व सुरक्षित बनी रहे।

महादेव ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट

सीबीआई ने सौराभ चंद्राकर की 10 दिन की रिमांड मंजूर कर ली, लोकसेवकों की पहचान पर जोर



यश भारत

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में मुख्य आरोपी और प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई ने 10 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली ले गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 12 नवंबर तक उनकी रिमांड मंजूर की है।

अदालत में सीबीआई ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि से अब तक सट्टेबाजी के जरिए हर महीने करीब साढ़े चार सौ करोड़ रुपये की अवैध कमाई हो रही थी। एजेंसी के मुताबिक, उन लोकसेवकों की पहचान करना भी जरूरी है, जिन्होंने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी में अवैध रूप से आर्थिक लाभ लिया है।

महादेव बुक का सिंडिकेट दुबई से संचालित होता था, जिसे इसका मुख्यालय बताया गया है। छत्तीसगढ़ के कई युवाओं को इस नेटवर्क में कर्मचारी, मैनेजर और सुपरवाइजर के रूप में लगाया गया था।

सीबीआई ने अदालत से कहा है कि सौरभ चंद्राकर से हिरासत में पूछताछ के बिना पूरे आपराधिक नेटवर्क का खुलासा करना संभव नहीं है। एजेंसी को अन्य मास्टरमाइंड, सहयोगियों, हवाला ऑपरेटरों और कथित लाभार्थियों की पहचान करनी है। इसके अलावा अवैध कमाई को एकत्र करने, विभिन्न स्तरों पर भेजने और विदेश में निवेश करने के तरीकों का पता लगाना है। महादेव ऐप के संचालन के लिए अवैध लाभ लेने वाले सरकारी कर्मचारियों की पहचान भी जरूरी बताई गई है।

यह मामला पहले छत्तीसगढ़ के ईओडब्ल्यू में दर्ज था। बाद में केंद्र और राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के आधार पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई।

गिरफ्तारी और पृष्ठभूमि

सौरभ चंद्राकर को ओमान में फर्जी यात्रा दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से प्रवेश करने के मामले में हिरासत में लिया गया था। ओमान सरकार ने उन्हें भारत को सौंप दिया। भारत पहुंचने पर 1 नवंबर को रात 7:35 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे पहले अदालत ने 9 सितंबर 2026 को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। 2 नवंबर को दिल्ली की अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उन्हें रायपुर लाया गया।

कैसे चल रहा था सिंडिकेट

सीबीआई के अनुसार, महादेव बुक ऐप का संचालन सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल सहित अन्य सहयोगियों द्वारा किया जा रहा था। ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म तैयार किए गए थे और पैनल ऑपरेटरों के माध्यम से कारोबार चलाया जाता था। इस अवैध कारोबार से प्रतिमाह करीब 450 करोड़ रुपये की कमाई होती थी। इसमें 70 से 80 प्रतिशत रकम प्रमोटर अपने पास रखते थे और शेष पैनल ऑपरेटरों को दी जाती थी। अवैध कमाई के लेन-देन के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाते खुलवाए गए थे। सट्टे से प्राप्त रकम को विभिन्न बैंक खातों और हवाला नेटवर्क के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भेजा जाता था। इस रकम का इस्तेमाल सट्टेबाजी वेबसाइटों के प्रचार, विज्ञापन और बड़े आयोजनों में भी किया जाता था।

संरक्षण राशि और जांच का दायरा

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि सट्टा कारोबार को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए विभिन्न पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों और प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों को संरक्षण राशि दी जाती थी। हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से इस रकम का वितरण किया जाता था। जांच एजेंसी के मुताबिक इस मामले में पुलिस, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक व्यक्तियों की भूमिका के साथ ही अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की भी जांच की जानी है।

दीपावली की आहट के साथ गूंजने लगे सुआ गीत, गांवों में आज भी जीवंत है छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति

आधुनिकता की दौड़ में शहरों से सिमटती जा रही पारंपरिक विरासत, ग्रामीण अंचलों में बालिकाएं और महिलाएं संभाल रही सांस्कृतिक परंपरा की कमान

गरियाबंद। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में पारंपरिक लोकगीतों और लोकनृत्यों की गूंज सुनाई देने लगती है। इन्हीं लोक परंपराओं में सुआ नृत्य का विशेष स्थान है। महिलाओं और युवतियों द्वारा गोल घेरा बनाकर तालियों की थाप पर सुआ गीत गाते हुए किया जाने वाला यह पारंपरिक नृत्य छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक संस्कृति और ग्रामीण जीवन की सुंदर पहचान है। सुआ गीतों की मधुर धुन और नृत्य की लयबद्ध प्रस्तुति देखकर मन आनंदित हो उठता है।

सुआ नृत्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति, लोक आस्था, सामाजिक परंपरा और भावनाओं से जुड़ी एक अनमोल विरासत है। इसका संबंध मुख्य रूप से नई फसल के आगमन, धान की कटाई की खुशी और प्रकृति के प्रति आभार से माना जाता है। लोकगीतों में भगवान शिव-पार्वती के गौरा-गौरी विवाह प्रसंग और लोक



जीवन से जुड़ी अनेक कथाओं की झलक भी देखने को मिलती है।

इस नृत्य की सबसे खास विशेषता है सुआ अर्थात तोते का प्रतीक। महिलाएं मिट्टी या लकड़ी से बने तोते को धान अथवा अनाज से भरी टोकरी के बीच स्थापित करती हैं। इसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर महिलाएं और बालिकाएं सामूहिक रूप से गीत गाती हैं और तालियों की थाप पर नृत्य करती हैं। लोकमान्यता के अनुसार सुआ को संदेशवाहक माना जाता है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपने मन की भावनाएं और संदेश अपने प्रिय(देवी-देवताओं)तक पहुंचाने की कल्पना करती हैं। गीतों में प्रेम, विरह, पारिवारिक जीवन, सामाजिक परिस्थितियों और धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति होती है।

एक समय था जब सुआ नृत्य केवल ग्रामीण अंचलों तक सीमित नहीं था, बल्कि धीरे-धीरे शहरों और सार्वजनिक सांस्कृतिक आयोजनों में भी अपनी पहचान बना रहा था। लेकिन बदलती जीवनशैली, आधुनिक मनोरंजन के साधनों और नई पीढ़ी की बदलती रुचियों के बीच यह परंपरा कई स्थानों पर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। विकास और आधुनिकता ने जहां जीवन को सुविधाजनक बनाया है, वहीं कहीं न कहीं हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत पर भी इसका प्रभाव पड़ा है।

छत्तीसगढ़ अपनी विशिष्ट लोककला, लोकगीत, नृत्य, तीज-त्योहार और परंपराओं के लिए देशभर में अलग पहचान रखता है। ऐसे में सुआ नृत्य जैसी सांस्कृतिक धरोहर का धीरे-धीरे सीमित होते जाना चिंता का विषय है। हालांकि छुरा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बालिकाएं और महिलाएं इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभा रही हैं। दीपावली के पहले गांवों में सुआ गीतों की गूंज इस बात का प्रमाण है कि लोक संस्कृति की जड़ें आज भी ग्रामीण समाज में मजबूत हैं।

सुशासन परिसर एवं पंचायत कैफ़े के निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

सुकमा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में सुशासन की अवधारणा को धरातल पर साकार करने तथा ग्रामीणों को बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्माणाधीन सुशासन परिसर एवं पंचायत कैफ़े के कार्यों को गति देने की दिशा में जिला प्रशासन ने सक्रिय पहल की है। कलेक्टर अमित कुमार के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुन्द ठाकुर ने बुधवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर प्रगति का जायजा लिया। बैठक में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायतों के तकनीकी सहायक, सचिव एवं सरपंच उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में ठाकुर ने प्रत्येक निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति का बारीकी से आकलन करते हुए अधिकारियों एवं मैदानी अमले को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाएं। निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही अथवा उदासीनता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्यों को समय पर पूर्ण नहीं करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखने तथा नियमित स्थल निरीक्षण कर कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

किसान सभा ने कोल परिवहन को रोककर किया चक्काजाम

कोरबा। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने एसईसीएल की कुसमुंडा खदान क्षेत्र में आउट सोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से होने वाले कामों में प्रभावित भू विस्थापितों और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कुसमुंडा थाना के पास कुसमुंडा से गुजरने वाली कोल परिवहन को पूर्ण रूप से रोककर चक्काजाम शुरू कर दिया चक्काजाम को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल उपस्थित था। चक्काजाम से खदान के अंदर और बाहर भारी वाहनों का जाम लगना शुरू हुआ जिसके बाद दर्री तहसीलदार और कुसमुंडा थाना प्रभारी ने थाना में किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल को त्रिपक्षीय वार्ता के लिए बुलाया बैठक में एसईसीएल ने 11 नवंबर को प्रशासन की उपस्तिथि में समस्याओं के समाधान का लिखित आश्वासन दिया उसके बाद चक्काजाम समाप्त हुआ।



छत्तीसगढ़ किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत झा ने प्रशासन से मांग किया की एसईसीएल में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण हुई है वह भू विस्थापित रोजगार के लिए भटक रहे हैं और प्रबंधन आऊट सोर्सिंग कंपनियों के साथ सांठ गांठ कर दूसरे जिलों और प्रदेशों से कर्मचारी लाकर भर्ती कर रही है। जिसका हमारे संगठन द्वारा विरोध किया जा रहा है कुसमुंडा और गेवरा में होने वाले कार्यों में प्रभावितों को प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण प्रभावित भू विस्थापित और स्थानीय बेरोजगारों को सड़क पर उतर कर विरोध करना पड़ रहा है।

किसान सभा के जिला अध्यक्ष जय कौशिक और सचिव दीपक साहू ने कहा की खदान विस्तार के लिए ग्रामीणों की पूरी जमीन ली जाती है लेकिन रोजगार देते समय 100: रोजगार प्रभावित ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा है 30: कंपनी सुरक्षित रखते हुए जिले से बाहर के लोगों को भरकर प्रभावितों के हक के रोजगार को बेच रही है। छोटे रकबा वाले किसानों को खेती किसानी से अलग कर पहले ही बेरोजगार बना दिया गया है और रोजगार होने के बावजूद किसानों को रोजगार से वंचित रखा जा है। प्रभावितों के पास अब संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर प्रबंधन ने प्रभावित क्षेत्र के भू विस्थापितों की बात नहीं सुनी तो आगे और उग्र आंदोलन होगा।

भू-विस्थापित नेता दामोदर श्याम और रेशम यादव ने आरोप लगाया कि जिनकी जमीन गई है उन्हें ना तो स्थाई रोजगार दिया जा रहा है ना ही उनके परिवार को आऊट सोर्सिंग में काम सभी के हक को निजी कंपनी छीनने का कार्य कर रही है। भू विस्थापित नेताओं ने इसके विरोध में एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र में उग्र प्रदर्शन कर चक्काजाम किया है और आगे भी सही नीति नहीं बनी तो आंदोलन का विस्तार होगा।

अराजकता हटाओ' आखिर किसके खिलाफः तारिणी चंद्राकर

धमतरी। जिला कांग्रेस कमेटी धमतरी के अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने भारतीय जनता पार्टी के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा आखिर किससे लोकतंत्र को बचाने और किसकी अराजकता हटाने की बात कर रही है? देश में केंद्र की सत्ता भाजपा के पास है और कई राज्यों में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में जनता यह जानना चाहती है कि लोकतंत्र को खतरा किससे है और अराजकता फैलाने वाला कौन है? भाजपा के पास आज जनता के बीच जाकर बताने के लिए विकास, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, युवाओं के रोजगार और आम आदमी की समस्याओं पर ठोस जवाब देने के बजाय राजनीतिक नारों और आरोप-प्रत्यारोप का सहारा लेने की स्थिति बन गई है। जनता के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नए-नए अभियान चलाए जा रहे हैं। भाजपा को यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र केवल रैली निकालने, नारे लगाने और सत्ता में बने रहने का नाम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ जनता की आवाज सुनना विपक्ष को सम्मान देना, सवालों का जवाब देना और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी का स्पष्ट कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी है। उनका आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और जनता की आवाज को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

दीपावली से पहले नगर पंचायत छुरा की पहल, वार्डों में बिछ रही मुरुम की परत

त्योहार पर नगरवासियों को मिलेगी राहत, खराब रास्तों को दुरुस्त करने में जुटी नगर पंचायत; सरकार की जनकल्याणकारी सोच और विधायक के विकास विजन को मिल रही गति

गरियाबंद। दीपावली के पावन पर्व से पहले नगर पंचायत छुरा द्वारा नगरवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न वार्डों में मुरुम डालकर खराब एवं असमतल रास्तों को दुरुस्त कराया जा रहा है। जिन स्थानों पर रास्तों की स्थिति खराब है और लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है, वहां आवश्यकता के अनुसार मुरुम डालकर रास्तों को समतल बनाने का कार्य किया जा रहा है। नगर पंचायत की इस पहल से त्योहार के दौरान नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी सोच के अनुरूप नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पंचायत छुरा द्वारा दीपावली को ध्यान में रखते हुए आवश्यक स्थानों पर सुधार कार्य कराए जा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू के



विकास विजन के अनुरूप नगर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में भी ऐसे कार्य महत्वपूर्ण हैं।

दीपावली नजदीक आते ही छुरा के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। नगर के साथ-साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंचते हैं। ऐसे में खराब रास्तों के कारण नागरिकों को असुविधा न हो, इसे ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत द्वारा वार्डों में जरूरत के अनुसार मुरुम डालने का कार्य कराया जा रहा है। बारिश के कारण कई स्थानों पर रास्ते खराब एवं असमतल हो गए थे। इन स्थानों पर मुरुम डालकर आवागमन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे दोपहिया वाहन चालकों, पैदल चलने वाले नागरिकों, बुजुर्गों और बच्चों को राहत मिलने की उम्मीद है।

नगर पंचायत अध्यक्ष लुकेश्वरी थानसिंह निषाद ने कहा कि दीपावली खुशियों, रोशनी और आपसी सद्भाव का पर्व है। त्योहार के अवसर पर नगरवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पंचायत की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से आवश्यकता वाले स्थानों पर मुरुम डालकर रास्तों को दुरुस्त कराया जा रहा है। नगर की साफ-सफाई, नालियों की सफाई और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि नागरिकों को त्योहार के दौरान स्वच्छ एवं सुविधाजनक वातावरण मिल सके।

नगर पंचायत का प्रयास है कि दीपावली के दौरान किसी भी वार्ड के नागरिकों को खराब रास्तों के कारण अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न स्थानों पर सुधार कार्य कराकर नगर को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। नगरवासियों को उम्मीद है कि त्योहार से पहले किए जा रहे इन कार्यों से आवागमन आसान होगा और दीपावली का पर्व उत्साह, उमंग एवं खुशियों के साथ मनाया जा सकेगा।

दिवंगत विधायक स्व. डोमनलाल कोर्सेवाड़ा को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

पुष्प अर्पित कर किया नमन, शोकाकुल परिजनों से मिलकर बंधाया ढांढस

यश भारत





रायपुर। दिवंगत विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बुधवार को बालोद जिले में उनके गृह ग्राम भेंड्रा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, सांसद विजय बघेल, विधायक ललित चंद्राकर, सतनामी समाज की गुरू दीदी प्रियंका, पूर्व विधायक सांवलाराम डाहरे सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने दिवंगत स्व. डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि डोमनलाल कोर्सेवाड़ा का निधन समाज और जनजीवन के लिए अपूरणीय क्षति है। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान, जनसेवा के प्रति समर्पण और लोगों से उनके आत्मीय जुड़ाव को सदैव याद किया जाएगा।

उनका स्नेह, सरल व्यवहार और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता लोगों के हृदय में हमेशा बनी रहेगी।

इस दौरान सभी ने शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस कठिन समय में उन्हें संबल प्रदान किया तथा दिवंगत आत्मा की शांति एवं परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारणी पुष्पेन्द्र चंद्राकर, नगर पालिका दल्लीराजहरा के अध्यक्ष तोरन लाल साहू, नगर पंचायत गुण्डरदेही के अध्यक्ष प्रमोद जैन, कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा सहित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

दीपावली से पहले बुनकरों और महिला स्व-सहायता समूहों को सौगात

9 करोड़ 41 लाख रुपये का पारिश्रमिक सीधे बैंक खातों में



यश भारत



रायपुर। दीपावली के पावन पर्व से ठीक पहले छत्तीसगढ़ के बुनकरों और सिलाई कार्य से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप और ग्रामोद्योग मंत्री श्री गजेन्द्र यादव के विशेष निर्देशों के तहत, राज्य सरकार ने बुनकर सहकारी समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को उनके श्रम का पारिश्रमिक जारी कर दिया है। इसके तहत कुल 9 करोड़ 41 लाख रुपये की राशि आरटीजीएस (त्नज्ञतस्) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है। समय पर भुगतान होने से इन परिवारों में दीवाली की खुशियां और अधिक दोगुनी हो गई हैं।

ग्रामोद्योग मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने इस संबंध में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बुनकरों और महिला स्व-सहायता समूहों के कठिन परिश्रम का समय पर पारिश्रमिक भुगतान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार स्थानीय हुनर को रोजगार से जोड़कर बुनकरों और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दीपावली से पहले पारिश्रमिक मिलने से उनके परिवारों के जीवन में उत्साह और समृद्धि का संचार होगा।

मंत्री श्री यादव ने आगे जोर देते हुए कहा कि वोकल फॉर लोकल की भावना को आत्मसात करते हुए बुनाई और गणवेश (यूनिफॉर्म) सिलाई के जरिए जमीनी स्तर पर सतत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं के कौशल विकास और स्वरोजगार के दायरे को बढ़ाकर उनकी आय में वृद्धि करना सरकार का मुख्य ध्येय है।

ग्रामोद्योग विभाग के सचिव सह प्रबंध संचालक श्री राजेश सिंह राणा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष और त्योहारी सीजन के दौरान पारिश्रमिक का यह वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे खातों में किया गया है। प्रदेश के 26 जिलों की 302 बुनकर सहकारी समितियों को 7 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान अक्टूबर 2026 में किया गया। 49 बुनकर सहकारी समितियों को 1 करोड़ 50 लाख रुपये तथा 128 महिला स्व-सहायता समूहों को 31 लाख रुपये का पारिश्रमिक 3 नवंबर को अतिरिक्त भुगतान किया गया।

राज्य हाथकरघा संघ द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3 नवंबर तक कुल 76 करोड़ 13 लाख 54 हजार रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा चुकी है, जिसमें शामिल हैं। बुनकर सहकारी समितियों को 345 बुनकर सहकारी समितियों को बुनाई पारिश्रमिक के रूप में 54 करोड़ 87 लाख रुपये, 2005 महिला स्व-सहायता समूहों को सिलाई पारिश्रमिक के रूप में 21 करोड़ 17 लाख रुपये की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा चुकी है।

बुनकरों की आकस्मिक मृत्यु पर 29 आश्रित परिवारों को 5 लाख 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान और हाथकरघा क्षेत्र के 11 पुरस्कृत हितग्राहियों को 3 लाख 74 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

पारंपरिक कार्यों के साथ-साथ सुदूर और आकांक्षी जिलों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की अनूठी पहल भी शुरू की गई है। इसके तहत सुकमा, बस्तर, कोरबा एवं जशपुर जिलों की 30 पुनर्वासित महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का विशेष प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है।

राज्य हाथकरघा संघ के अनुपयोगी और कटपीस वस्त्रों का सदुपयोग करते हुए इनसे आकर्षक खिलौने, थैले (बैग) और वाटर बैग जैसे उत्पाद तैयार करवाने के कार्यादेश दिए जा रहे हैं। साथ ही, इन महिलाओं को घर पर ही निःशुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध कराकर उनके लिए आय के नए और स्थायी अवसर विकसित किए जा रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ: रायपुर में की पदयात्रा, कांग्रेस पर जमकर बरसे नेता



रायपुर। छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर में 5 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा और रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के नेतृत्व में दोपहर 3 बजे सुभाष स्टेडियम परिसर से नगर घड़ी चौक तक पदयात्रा निकाली गई।

पदयात्रा से पहले सुभाष स्टेडियम परिसर में आयोजित सभा में रायपुर शहर और रायपुर ग्रामीण के हजारों भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य अराजकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो सब ठीक रहता है, लेकिन चुनाव हारने के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगती है।

वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ा रही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम इस पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देंगे।सभा को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने भी संबोधित किया। भाजपा नेताओं ने इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस की नीतियों और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। रायपुर में आयोजित इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया।

दीपावली पर दो दिन बंद रहेगा रायपुर जंगल सफारी और जू, 10-11 को पर्यटकों की एंट्री पर रोक

रायपुर। दीपावली के मद्देनजर राजधानी रायपुर स्थित जंगल सफारी एवं जू प्रशासन ने पर्यटकों के प्रवेश पर दो दिनों के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। जारी आदेश के अनुसार, 10 और 11 नवंबर को जंगल सफारी और जू पूरी तरह पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। प्रशासन ने यह कदम दीपावली के दौरान संभावित अप्रिय घटनाओं को रोकने, सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाने और वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या अनहोनी की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र संचालक, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व, रायपुर की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत निर्धारित दोनों दिनों तक पर्यटकों को प्रवेश नहीं मिलेगा।

सनातन धर्म प्रेमियों को धनतेरस ,दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गौरी गौरा पूजा की दी बधाई

रायपुर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सह विभाग मंत्री बंटी कटरे ने समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को धनतेरस ,दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गौरी गौरा पूजा की ढेरो शुभकामनायें दी , रायपुर विभाग सह मंत्री बंटी कटरे ने कहा कि श्री राम मंदिर अयोध्या बनता हुवा जो देख रहे है निर्णायक स्थिति पर लाने वाले हिंदुत्व का परचम लहराने वाले श्रद्धेय अशोक सिंगल के जन्म शताब्दी वर्ष पर नमन करते है संगठित हिंदू समर्थ भारत अखंड भारत हो, इस दीपावली एक दिप अपने हिंदू समाज को समरस करने समरसता का भाव जगाने एक दिप जलाये, छुवा छुत जात पात की इस छुवा छुत की बीमारी को दूर कर हिंदू समाज समरस हो, अपने देश धर्म संस्कृति के उत्थान हेतू, मिल जुल कर कार्य करे, विभाग मंत्री द्वारा समाज से एक अपील की गई है, कोई भी सामान वस्तु ऑनलाइन खरीदारी ना करे, स्थानीय व्यवसाइयो से ही खरीदारी करे, जो हिंदू समाज के पर्व मानता हो। सहयोग करता हो ऐसे लोंगो से खरीदारी करे, पुनः दीवाली की ढेरो शुभकामनायें समस्त हिंदू समाज को।

किसानों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाएंगे 'किसान मितान', हर बूथ पर 10 कार्यकर्ता जोड़ने की तैयारी : बंशीलाल गुर्जर

यश भारत



रायपुर। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा किसान मोर्चा की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा शुरू किए जा रहे 'किसान मितान' अभियान को संगठन विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में गुर्जर ने कहा कि किसान मितान के माध्यम से प्रत्येक मतदान केंद्र पर 10-10 कार्यकर्ताओं को जोड़ने की योजना है। ये कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर किसानों से संपर्क करेंगे और उनकी वास्तविक समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी सरकार तक पहुंचाएंगे, ताकि उनका समय पर समाधान किया जा सके।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 82 प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के वादे को पूरा कर रही है। प्रदेश में 3100 से अधिक धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। किसानों की यूनिक आईडी, डिजिटल सर्वे और बोए गए रकबे के आधार पर धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने तीन वर्षों में किसानों को आदान सहायता के रूप में लगभग 35 हजार करोड़ रुपये दिए हैं।

गुर्जर ने बताया कि धान के स्थान पर दलहन और अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से 15 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया।

केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। संकट की स्थिति में किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध हैं।

भाजपा का लोकतंत्र बचाओ अभियान चोरी ऊपर से सीना जोरी है – कांग्रेस

भाजपा का लोकतंत्र बचाओ अभियान ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए

यश भारत



रायपुर। भाजपा का लोकतंत्र बचाओ अभियान चोरी ऊपर से सीनाजोरी है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब वोट चोरी का षडयंत्र रंगे हाथों पकड़ा गया, तो भाजपा ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए मैदान में उतर आई। यह साबित करता है कि यह भाजपा का प्रायोजित वोटर डिलीट सिंडिकेट है। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र और बाबा साहब अंबेडकर के दिए संवैधानिक अधिकारों पर भाजपा सरकार ने डाका डालना शुरू कर दिया है। एसआईआर के नाम पर गरीब, किसान, मजदूर और आदिवासियों के नाम मतदाता सूची से षडयंत्रपूर्वक काटे गये। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस वोट चोरी का रंगे हाथों पर्दाफाश किया, तो बौखलाई भाजपा अपनी नाकामी छिपाने के लिए ज्ञानेश कुमार जी के बचाव में उतर आई है। भाजपा का यह बचाव ही साबित करता है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा द्वारा वोट चोरी के समर्थन में लोकतंत्र बचाओ रैली वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए है। देश के मतदाता अपने मतदान के अधिकार की चोरी के खिलाफ लामबंद है। युवा, छात्र, विपक्षी दल, आम आदमी सभी एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी के खिलाफ एकजुटता से खड़े है। भाजपा और चुनाव आयोग के गठबंधन के खिलाफ पूरे देश में वातावरण इससे घबरा कर भाजपा लोकतंत्र बचाओ अभियान चला रही है। भाजपा देश के मतदाताओं और नागरिकों को भीड़ तंत्र बताने का दुस्साहस कर रही है। इसी भीड़ तंत्र से भारत का लोकतंत्र पुष्पित और पल्लवित है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का उपयोग सुधार के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक छांटने के लिए किया जा रहा है। बीएलओ स्तर पर दबाव बनाकर, बिना वैधानिक सत्यापन और बिना पूर्व सूचना के गरीब, मजदूर, आदिवासी एवं ग्रामीण मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से विलोपित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का भूमिहीन मजदूर, आदिवासी और देहात का आम नागरिक, जो रोज़ी-रोटी के लिए पलायन करता है या दूरदराज में रहता है, उसके मौलिक संवैधानिक अधिकार, वोट देने के अधिकार पर सीधा डाका डाला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में वोटर डिलीट सिंडिकेट का पर्दाफाश हो चुका गया है, आरोप निर्वाचन आयोग के त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया से नाम काटने के षडयंत्र पर लग रहा है तो

जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के लिए मास्टर ट्रेनर्स के प्रथम बैच का प्रशिक्षण संपन्न

16 से 19 नवम्बर तक फील्ड ट्रेनर्स के प्रशिक्षण हेतु दूसरे बैच का आयोजन

राज्य में 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होगा जनगणना का मैदानी कार्य



रायपुर। भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण अर्थात् मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य छत्तीसगढ़ में 01 से 30 मई 2026 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब दूसरे चरण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। राज्य में इस चरण का मैदानी कार्य 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक किया जाएगा। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार के सदस्यों की गणना करेंगे।

जनगणना जैसे व्यापक राष्ट्रीय कार्य की सफलता के लिए प्रशिक्षित और दक्ष मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। दूसरे चरण में राज्यभर में लगभग 66 हजार प्रगणक एवं पर्यवेक्षक मैदानी स्तर पर कार्य करेंगे। इनके प्रशिक्षण के लिए जिलों द्वारा 1,120 फील्ड ट्रेनर्स नामित किए गए हैं। फील्ड ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करने के लिए जिलों से 47 और जनगणना कार्य निदेशालय से 13, कुल 60 मास्टर ट्रेनर्स नामित किए गए हैं।

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के मार्गदर्शन तथा जनगणना के नोडल एवं गृह विभाग की राज्य नोडल अधिकारी श्रीमती निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव और जनगणना कार्य निदेशालय, छत्तीसगढ़ के निदेशक श्री कार्तिकेया गोयल के दिशा-निर्देशों में मास्टर ट्रेनर्स का राज्यस्तरीय प्रशिक्षण नवा रायपुर अटल नगर स्थित प्रशासन अकादमी में आयोजित किया जा रहा है।

प्रशिक्षण दो बैचों में आयोजित किया जा रहा है। प्रथम बैच का चार दिवसीय प्रशिक्षण 02 नवम्बर से शुरू होकर 05 नवम्बर को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के लिए नामित राष्ट्रीय प्रशिक्षक श्री अशोक मिश्र और श्री प्रदीप कुमार साव, दोनों संयुक्त निदेशक, ने प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रथम बैच में 16 जिलों में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर- रामानुजगंज, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, बलौदाबाजार-भाटापारा और खैरागढ़-छुईखदान- गंडई के मास्टर ट्रेनर्स शामिल हुए। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को जनगणना के दूसरे चरण की प्रक्रिया, प्रश्नावली, प्रगणना की तकनीकी बारीकियों, मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग, आंकड़ों के संकलन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने सहित विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें आगे फील्ड ट्रेनर्स को प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया गया।

धान बेचने के लिए इस बार किसानों को केवल 60 दिन ही मिलेंगे

यश भारत

रायपुर । समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए इस बार किसानों को केवल 60 दिन ही मिलेंगे। धान खरीदी के लिए शासन ने इस बार 15 दिन की कटौती कर दी है। अब 15 नवंबर से 15 जनवरी तक ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी, जबकि पिछले साल 15 नवंबर से 31 जनवरी तक खरीदी हुई थी। इससे जांजगीर-चांपा जिले के किसानों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि जिले में ज्यादातर किसान लेट वैरायटी की फसल लेते हैं। धान खरीदी भले ही 15 नवंबर से शुरू हो जाती है, लेकिन जिले में धान की आवक दिसंबर महीने से ही शुरू होती है। दिसंबर और जनवरी के दो महीनों में ही बंपर आवक रहती है। ऐसे में इस बार किसानों को धान बेचने के लिए कम समय मिलेगा।

इससे खरीदी केंद्रों में भगदड़ जैसी स्थिति बन सकती है। ऊपर से यदि लिमिट का पेंच फंसा तो स्थिति और जटिल हो जाएगी। किसानों को तय समय में धान बेच पाने की चिंता सता रही है। पिछली बार 31 जनवरी तक खरीदी होने के बावजूद कई किसान धान बेचने से वंचित रह गए थे। किसानों की मांग को देखते हुए शासन ने खरीदी की अवधि कुछ दिन और बढ़ाई थी। लेकिन इस साल शासन ने पहले ही खरीदी की तारीख 15 दिन कम कर दी है।

हालांकि, इस बार पहले से पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उन्हें राहत मिली है। धान खरीदी का आदेश जिला सहकारी केंद्रीय बैंक समेत अन्य संबंधित विभागों में पहुंच गया है। खरीदी की समय-सीमा का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसानों तक यह जानकारी पहुंच सके।

समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए अब तक जिले में 1 लाख 28 हजार 719 किसानों ने पंजीयन कराया है। इनमें 4,193 नए किसान हैं, जो पहली बार धान बेचेंगे। पिछले साल जिले में 1 लाख 26 हजार किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था। इस बार धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए जिले में तैयारियां शुरू हो गई हैं। धान खरीदी के लिए नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। खरीदी प्रभारी भी तय किए जा रहे हैं।

संपादकीय

कर्ज की गिरफ्त में दम तोड़ती पारिवारिक खुशियां



भोपाल के मालीखेड़ी में कर्ज के बोझ से दबे नरेंद्र साहू द्वारा मां, पत्नी और दो मासूम बच्चों की हत्या के बाद खुद आत्महत्या कर लेने की घटना महज एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि हमारे बदलते सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर करारा तमाचा है। एक व्यक्ति पर हर महीने करीब 40 हजार रुपये ब्याज चुकाने का दबाव था। मकान, कार और बाइक बेचने के बाद भी कर्ज खत्म नहीं हुआ। आर्थिक दबाव के साथ अन्य परिस्थितियां भी इस घटना से जुड़ी बताई जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर कर्ज का बोझ इंसान को किस हद तक तोड़ रहा है और हमारा समाज ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए क्या कर रहा है?

आज कर्ज लेना जितना आसान हुआ है, उससे निकलना उतना ही कठिन होता जा रहा है। बैंक, फाइनेंस कंपनियां और निजी साहूकार हर जरूरत के लिए ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। बाजार ने भी एक ऐसी संस्कृति विकसित कर दी है, जिसमें जरूरत से ज्यादा इच्छाओं को महत्व दिया जा रहा है। महंगी गाड़ी, बड़ा मकान, ब्रांडेड सामान और भव्य आयोजन सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रतीक बना दिए गए हैं। लोग अपनी आमदनी नहीं, दूसरों की जीवनशैली देखकर खर्च करने लगे हैं। आसान किस्तों का आकर्षण भविष्य की आर्थिक परेशानियों को छिपा देता है। फिर एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया जाता है और परिवार ब्याज के ऐसे भंवर में फंस जाता है, जहां उसकी पूरी कमाई दूसरों की जेब में जाने लगती है।

सबसे खतरनाक स्थिति अवैध सूदखोरी की है। ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देने वाले लोग मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वसूली के नाम पर धमकी, अपमान और मानसिक प्रताड़ना व्यक्ति को भीतर तक तोड़ देती है। दूसरी ओर, वित्तीय संस्थानों की ऋण वसूली प्रक्रिया को भी मानवीय और जवाबदेह बनाने की जरूरत है। आर्थिक संकट किसी अपराध का औचित्य नहीं हो सकता, लेकिन संकटग्रस्त व्यक्ति को समय रहते सहायता न मिलना भी व्यवस्था की गंभीर विफलता है।

अब सरकार को केवल आर्थिक विकास और ऋण वितरण के आंकड़ों से आगे बढ़कर परिवारों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। अवैध सूदखोरी पर कठोर कार्रवाई, ऋण पुनर्गठन की सरल व्यवस्था, कानूनी सहायता और मानसिक परामर्श केंद्र स्थापित करना समय की मांग है। स्कूलों से ही वित्तीय साक्षरता की शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि नई पीढ़ी कर्ज और बचत का अंतर समझ सके।

समाज को भी आत्ममंथन करना होगा। आखिर हम आने वाली पीढ़ी को बचत और आत्मनिर्भरता की सीख देंगे या दिखावे के लिए कर्ज लेने की आदत? प्रतिष्ठा का पैमाना महंगी गाड़ी और आलीशान मकान नहीं, बल्कि कर्जमुक्त जीवन और खुशहाल परिवार होना चाहिए। भोपाल की घटना एक भयावह चेतावनी है। कर्ज की समस्या को केवल व्यक्ति की निजी विफलता मानकर छोड़ना घातक होगा। आर्थिक समृद्धि का वास्तविक अर्थ तभी है, जब बाजार की चमक के पीछे परिवारों का अंधेरा न छिपा हो।

कड़वे वचन



जीवन का यहनियम याद रखो। जो आप देने वाले हैं वह आपके पास लौटके आने वाला है। कई गुना बढ़कर आने वाला है। हर किसान यह नियम जानता है, मानता है और इस पर काम करता है। वह खेत में अच्छे व बेहतरीन बीज डालता है और फसल आने का इंतजार करता है। किसान यह जानता है मगर अफसोस है कि इंसान यह नहीं जानता। दिया कभी बेकार नहीं जाता । याद रखो दे जाना ही ल जाने का मार्ग है।

आज का राशिफल



ज्योतिषाचार्य पंडित लोकेश व्यास

पंचांगः-5 नवम्बर, 2026
दिन-गुरुवार, अश्विन शुक्ल 10
विक्रम संवत 2083

मेष चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ
दिन सामान्य रहने वाला है किसी की मदद करने से खुशी मिलेगी

वृष इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो
किसी विशेष कार्य को करने में दिन व्यतीत होगा लोगों की प्रशंसा मिल सकती है

मिथुन का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह
आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी दिन खुशनुमा रहने वाला है

कर्क ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो
मानसिक उलझनें कम हो सकती हैं खर्चों की अधिकता बनी रहेगी

सिंह मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे
दिन अनुकूल रहने वाला है माता-पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करें

कन्या ढो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो
धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं

तुला रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते
दिन उत्तम रहने वाला है सामाजिक कार्यों में गतिविधियां बढ़ेगी

वृश्चिक ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे
स्वास्थ्य में पहले से अब सुधार होगा योग प्राणायाम अवश्य करें

धनु ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे
घर में शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं मन प्रफुल्लित रहेगा

मकर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी
साझेदारी के काम को सोच समझ कर आगे बढ़ाएं क्रोध में नियंत्रण रखें

कुंभ गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा
खर्चों की अधिकता की वजह से आर्थिक स्थिति प्रभावित रहेगी

मीन दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची
वाणी में नियंत्रण रखकर कार्य करें दिन सामान्य रहने वाला है

धन्वंतरि की दिव्य विरासत और यमदीप की प्राचीन परंपरा

आरोग्य, धन और समृद्धि का पावन पर्व है धनतेरस



प्रतिवर्ष दीपावली से दो दिन पूर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 6 नवंबर को मनाया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में धनतेरस का विशेष धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसे केवल धन और वैभव की प्राप्ति का पर्व मानना उचित नहीं होगा बल्कि यह आरोग्य, दीर्घायु, सुख-समृद्धि और स्वस्थ जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर है। इस दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा-अर्चना की जाती है। धनतेरस का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। उन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार तथा आयुर्वेद का प्रवर्तक माना जाता है। मान्यता है कि उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था, जो जीवन, स्वास्थ्य और अमरत्व का प्रतीक है। इसी कारण उन्हें देवताओं का वैद्य और आरोग्य का देवता कहा जाता है। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत के माध्यम से देवताओं को अमरत्व प्राप्त हुआ था। भगवान धन्वंतरि के इसी दिव्य प्राकट्य की स्मृति में धनतेरस मनाने की परंपरा प्रचलित हुई।

भगवान धन्वंतरि का संबंध केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि उनका आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा परंपरा में भी विशेष स्थान है। आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान माना गया है, जिसका उद्देश्य केवल रोगों का उपचार करना नहीं बल्कि शरीर और मन को स्वस्थ रखते हुए दीर्घ एवं संतुलित जीवन प्रदान करना है। यही कारण है कि धनतेरस का दिन चिकित्सकों, वैद्यों और चिकित्सा जगत से जु? लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा कर लोग परिवार के आरोग्य, निरोगी काया और दीर्घायु की कामना करते हैं। धनतेरस हमें यह संदेश भी देता है कि वास्तविक धन केवल सोना, चांदी और संपत्ति नहीं बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति और संतोषपूर्ण जीवन है। इसलिए इस पर्व का मूल भाव धन के साथ आरोग्य और समृद्धि की मंगलकामना करना है।

धनतेरस के पर्व पर भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ मृत्यु के देवता यमराज के पूजन तथा दीपदान का भी विशेष विधान है। इस दिन संध्याकाल में घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर यमराज के निमित्त एक दीपक जलाया जाता है, जिसे 'यम दीपक' अथवा 'यमदीपदान' कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि तथा मंगल बना रहता है। इस परंपरा के पीछे एक अत्यंत रोचक और भावुक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार, एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि प्राणियों के प्राण हरते समय क्या कभी ऐसा अवसर भी आया, जब किसी व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में दया उत्पन्न हुई हो और तुम्हारा हृदय करुणा से भर उठा हो? यमराज का प्रश्न सुनकर यमदूतों ने उत्तर दिया कि वे तो केवल उनकी आज्ञा का पालन करने वाले सेवक हैं। उनका कार्य निर्धारित समय पर जीवों के प्राण लेना है, इसलिए दया और मोह-माया का उनके कार्य में कोई स्थान नहीं है। हालांकि, यमराज द्वारा निर्भय होकर सच बताने का आश्वासन दिए जाने पर उन्होंने एक ऐसी घटना का उल्लेख किया, जिसने उन्हें भी भीतर तक विचलित कर दिया था।

यमदूतों ने बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार के लिए जंगल में गया था। शिकार करते समय वह अपने साथियों से बिछु?कर दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। उस राज्य के राजा हेमा ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उसका खूब आदर-सत्कार किया। संयोगवश उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजपरिवार में खुशियां छा गई लेकिन ज्योतिषियों ने नवजात राजकुमार की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि विवाह के ठीक चार दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी शोकाकुल हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को इस अनिष्ट से बचाने के लिए उसे यमुना नदी के किनारे एक निर्जन गुफा में रखवा दिया। वहां उसके पालन-पोषण की राजसी व्यवस्था की गई और विशेष सावधानी बरती गई कि उस पर किसी युवती की छाया तक न प?े। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन संयोगवश राजा हंस की पुत्री घूमते-घूमते यमुना तट पर पहुंच गई। वहां उसकी दृष्टि राजकुमार पर प?ी और दोनों एक-दूसरे को देखते ही मोहित हो गए। उनके बीच प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसी समय गंधर्व विवाह कर लिया। दुर्भाग्यवश, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के चार दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। यमदूतों ने यमराज को बताया कि उन्होंने अपने जीवन में उस नवविवाहित जो? जैसा सुंदर और प्रेमपूर्ण युगल कभी नहीं देखा था। दोनों कामदेव और रति के समान प्रतीत होते थे। राजकुमार के प्राण हरने के बाद जब उसकी नवविवाहिता पत्नी ने विलाप करना शुरू किया तो उसका करुण क्रंदन सुनकर यमदूतों का हृदय भी द्रवित हो उठा। यह पूरा वृत्तांत सुनने के बाद यमराज ने कहा कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरि के पूजन के साथ उनके निमित्त दीपदान करने से अकाल मृत्यु के भय से रक्षा होती है। तभी से धनतेरस पर यमदीपदान की परंपरा प्रचलित होने की मान्यता है। इसी विश्वास के चलते लोग संध्याकाल में घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर यमराज से परिवार के सभी सदस्यों की लंबी आयु और आरोग्य की प्रार्थना करते हैं।

धनतेरस पर खरीदारी की भी विशेष परंपरा है। इस दिन पुराने और टूटे-फूटे बर्तनों के स्थान पर नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। अनेक लोग सोने-चांदी के आभूषण, सिक्के और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी खरीदते हैं। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आती हैं। कुछ परिवारों में नई झा? खरीदकर उसका पूजन करने की भी परंपरा है।

(लेखक- योगेश कुमार गोयल)

अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में ऐतिहासिक हार का महा झटका!

ट्रंप की वैश्विक साख पर प्रहार! टूटा भ्रम



वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे पुराने लोकतंत्र व विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या यूँ कहें कि पूरे विश्वपर अनौपचारिक रूप से राज करने वाले अमेरिका के मध्यावधि चुनावों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ ला दिया है। अभी वर्तमान विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा और सीनेट,दोनों में बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि अमेरिका के इतिहास में यह कोई पहली बार नहीं हुआ है।पिछले 20 वर्षों में पांच मिडटर्म चुनाव हुए। इन सभी में राष्ट्रपति की पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में सीटें गंवाईं। यह परिणाम केवल विपक्ष की चुनावी सफलता नहीं, बल्कि महंगाई, जीवन- यापन की लागत, ईरान युद्ध और ट्रंप प्रशासन की नीतियों के प्रति मतदाताओं की नाराजगी का संकेत भी है, ऐसा माना जा रहा है कि जिसका पहले से ही अंदेशा भी था? मीडिया के अनुसार, विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत के लिए आवश्यक 218 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया और सीनेट पर भी नियंत्रण हासिल किया।चुनावी गणित-कांग्रेस के दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स की वापसी करीब करीब सुनिश्चित हो गई है प्रतिनिधि सभा 225 - डेमोक्रेट्स 137 रिपब्लिकन सीटें घोषित बहुमत- 218 / 435 सीनेट 51+, डेमोक्रेटिक गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार,बहुमत- 51/ 100,4 नवंबर को उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार,प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट्स ने 225 और रिपब्लिकन ने 137 सीटें जीत ली थीं, बस मिनट में 54 सीटें प्राप्त कर ली थी,जबकि शेष सीटों पर मतगणना जारी थी। सीनेट में भी डेमोक्रेट्स नेरिपब्लिकन बहुमत समाप्त कर दिया। कई महत्वपूर्ण रिपब्लिकन सीटों पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों की जीत ने सत्ता का संतुलन बदल दिया। अंतिम प्रमाणित सीटों की संख्या राज्यवार मतगणना और प्रमाणन के बाद स्पष्ट होगी। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की तुलना भारत की संसद से की जा सकती है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा भारत की लोकसभा के समान जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है। इसकी सभी 435 सीटों पर हर दो वर्ष में चुनाव होता है। अमेरिकी सीनेट भारत की राज्यसभा की तरह एक उच्च सदन है, लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर हैं। अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य से दो,और उनका कार्यकाल छह वर्ष होता है।भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, वर्तमान संवैधानिक सीमा के अंतर्गत 245 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा स्थायी सदन है और इसके लगभग एक- तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।

साथियों बात अगर हम ट्रंप की हार

कार्यकाल नहीं, राजनीतिक शक्ति पर असर को समझने की करें तो मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है। ट्रंप का चार वर्ष का राष्ट्रपति कार्यकाल जनवरी 2029 तक जारी रहेगा। चुनाव में हार से उनका कार्यकाल छोटा नहीं होगा, लेकिन कानून पारित करना, बजट मंजूर कराना और प्रशासनिक नियुक्तियों को आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है।डेमोक्रेटिक बहुमत वाली समितियां अब ट्रंप प्रशासन के फैसलों,सरकारी खर्च, आव्रजन नीति, व्यापारिक टैरिफ और युद्ध संबंधी निर्णयों की जांच कर सकती हैं।महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है, लेकिन केवल चुनाव हारने से महाभियोग स्वतः नहीं होता। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रतिनिधि सभा में महाभियोग और सीनेट में दोषसिद्धि के लिए दो-तिहाई समर्थन आवश्यक है।पिछले 20 वर्षों में2006 2010, 2014, 2018 और 2022 के पांच मिडटर्म चुनाव हुए। इन सभी में राष्ट्रपति की पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में सीटें गंवाईं। जॉर्ज डब्ल्यू. बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के कार्यकालों में यह राजनीतिक पैटर्न दिखाई दिया। सीनेट में स्थिति अलग रही- 2006 और 2014 में राष्ट्रपति की पार्टी ने नियंत्रण गंवाया, जबकि 2010, 2018 और 2022 में बहुमत बरकरार रखा या मजबूत किया। यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति बताती है कि मिडटर्म चुनाव अक्सर राष्ट्रपति के लिए जनमत की सटीकता से परीक्षा होते हैं। साथियों बात अगर हम अब ट्रंप की नीतियों का क्या होगा? इसको समझने की करें तो,डेमोक्रेटिक नियंत्रण से ट्रंप की नीतियों पर संसदीय अंकुश बढ़ेगा, लेकिन उनकी सभी नीतियां स्वतः समाप्त नहीं होंगी।टैरिफ और अमेरिका फर्स्ट- कांग्रेस को विदेशी व्यापार और आयात शुल्क पर संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को कुछ कानूनों के अंतर्गत टैरिफ लगाने की शक्तियां भी मिली हैं। डेमोक्रेट्स टैरिफ से जुड़े कानूनों, बजट और प्रशासनिक फैसलों की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन हर टैरिफ को तत्काल समाप्त नहीं कर सकते।आव्रजन और वीजा- भारतीय छात्रों,आईटी पेशेवरों और एच -1बी वीजा धारकों के लिए अधिक निष्पक्ष आव्रजन नीति की संभावना बन सकती है।हालांकि वीजा नियमों मेंबदलाव के लिए प्रशासनिक निर्णय, कानून और संबंधित एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। तत्काल वीजा राहत की गारंटी नहीं है।वेनेजुएला और विदेश नीति- वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने जैसे राजनीतिक बयानों को वास्तविक नीति या संवैधानिक प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। कांग्रेस विदेश नीति, सैन्य खर्च और प्रतिबंधों पर निगरानी बढ़ा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां बनी रहेंगी।

साथियों बात अगर हम इस मिड टर्म चुनाव 3 नवंबर 2026 में भारतीय-अमेरिकी और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका को समझने की करें तोमिशिगन में 42 वर्षीय डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद ने रिपब्लिकन माइक रोजर्स को हराकर अमेरिकी सीनेट में पहुंचने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति बनने का इतिहास रचा।उन्होंने स्वास्थ्य सेवा,जीवन-यापन की लागत और राजनीति में कॉरपोरेट धन के प्रभाव को अपने अभियान का केंद्र बनाया। ट्रंप के तीखे हमलों के बावजूद उनकी जीत ने मुस्लिम -अमेरिकी समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नई पहचान दी।हालांकि मुस्लिम और भारतीय- अमेरिकी मतदाताओं ने कितने प्रतिशत वोट देकर चुनाव परिणाम बदल दिया, इसका सटीक राष्ट्रीय आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है,

(लेखक-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी)

पारिवारिक रिश्तों में जहर घोल रही है डिजिटल सौतन



आज मोबाइल पर रील ओटीटी चैनल पर बढ़ता स्क्रीन टाइम पारिवारिक माहौल में जहर घोलने का काम कर रहा हैं। परिजनों के बीच भी बैठे एक ही परिवार के सदस्यों के बीच वार्तालाप के समय को इस डिजिटल सौतन ने छीन लिया है। डाइनिंग टेबल हो या ड्राइंग रूम सब की मौजूदगी में भी सब अकेले है। यह एक कटु सच्चाई है आपसी रिश्ते मोबाइल और सोशल मीडिया के निशाने पर हैं।

हाल ही में एक ऐसा ही मामला काफी सुर्खियों में आ गया जब एक ही छत के नीचे रहने वाले वरिष्ठ चिकित्सक दंपती के बीच मोबाइल डिजिटल सौतन बन गया है। पति सर्जन और पत्नी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। पति को यूट्यूब पर वीडियो देखने की लत दो वर्ष पहले पड़ी। वह घर आने के बाद पत्नी से बात करने की जगह मोबाइल पर वीडियो देखने लग जाते हैं। इससे पत्नी चिढ़ने लगीं, पति को समझाने का प्रयास किया। लत नहीं छूटी।

आगरा का यह मामला इसी गंभीर स्थिति का एक सटीक और बेहद चौंकाने वाला उदाहरण है। आगरा पुलिस के परिवार परामर्श केंद्र में हाल ही में आया यह केस यह साबित करता है कि मोबाइल एडिक्शन किसी भी वर्ग या पेशे के व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है।

इस पूरे मामले के मुख्य बिंदुओं पर नजर डाल लीजिए। इस मामले में पति एक सर्जन हैं और पत्नी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। दोनों ही उच्च शिक्षित और प्रतिष्ठित पेशेवर हैं।

डॉक्टर पति को पिछले दो साल से यूट्यूब पर वीडियो और रील्स देखने की गंभीर लत लग गई थी। अस्पताल से घर लौटने के बाद वे पत्नी से बात करने के बजाय घंटों मोबाइल स्क्रीन में खोए रहते थे।

पत्नी ने काउंसलिंग के दौरान अपनी नाराजगी और लाचारी जाहिर करते हुए एक बेहद तीखी बात कही। उन्होंने कहा, वीडियो देखने से अच्छा है कि पति नशा या शराब ही पी लिया करें, कम से कम उस बहाने मुझसे बात तो करेंगे। यह बयान दिखाता है कि पार्टनर की डिजिटल अनदेखी किसी को किस हद तक मानसिक रूप से आहत कर सकती है।

आगरा कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर और काउंसलर्स के मुताबिक, इस दंपती की दो बार काउंसलिंग की जा चुकी है, जिसके बाद उनके बीच का तनाव और कड़वाहट धीरे-धीरे कम हो रही है।

आगरा पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि वहां आने वाले वैवाहिक विवादों के कुल मामलों में से 35 से 40 प्रतिशत मामले केवल मोबाइल स्क्रीन टाइम और डिजिटल एडिक्शन के कारण आ रहे हैं। अब शराब की लत या पारिवारिक हस्तक्षेप से भी बड़ी वजह यह डिजिटल सौतन बनती जा रही है

अकेले में मोबाइल की स्क्रीन देखकर अपने चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। यह अकेला मामला नहीं है, पति-पत्नी के बीच मोबाइल डिजिटल सौतन की जगह ले रहा है। घर और परिवार से दूर रहने वालों के बीच दूरियां कम करने वाला मोबाइल एक छत के नीचे रहने वाले पति-पत्नी के बीच अनदेखी डिजिटल दीवार खड़ी कर रहा है।घर में मोबाइल को अधिक समय देना, बार-बार वाट्सएप चेक करना और चैट करना पति-पत्नी के रिश्तों में रार पैदा कर रहा है। परिवार परामर्श केंद्र में वर्तमान में एक हजार से अधिक मामले पहुंचे, जिनमें 35 से 40 प्रतिशत मामले मोबाइल के चलते होने वाली रार के थे। पिछले तीन वर्ष मे इस तरह के मामलों में बढोत्तरी हुई है। इससे पहले पति-पत्नी का एक दूसरे पर किसी और से प्रेम संबंध होने का शक करने के मामले अधिक थे। एक अध्ययन में अमेरिका के 40,337 बच्चों और किशोरों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था। इसमें पाया गया कि 14 से 17 साल के जिन किशोरों ने रोजाना सात घंटे या उससे अधिक स्क्रीन का इस्तेमाल किया उनमें एक घंटे तक स्क्रीन इस्तेमाल करने वालों की तुलना में डिप्रेशन या एंग्जायटी में होने की संभावना दोगुने से ज्यादा थी। लेकिन यह अध्ययन दोनों के बीच संबंध दिखाता है इसमें यह साबित नहीं होता है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम ही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का एकमात्र कारण है। फिर भी इस आकड़े के नतीजे से डिजिटल आदतों पर ध्यान देने की जरूरत बढ़ जाती है।

अगर आप अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहते है तो इसकी शुरुआत छोटे बदलावों से की जा सकती है। जिसमें खाना खाते समय फोन दूर रखें, दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत के दौरान नोटिफिकेशन बंद करें और दिन में कुछ समय टहलने, व्यायाम करने या कोई नया शौक सीखने के लिए निकालना शुरू कर दें। वहीं सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल सीमित करना और बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नजर रखना भी उपयोगी हो सकता है। इसमें ध्यान रखें कि काम, पढ़ाई और मनोरंजन के लिए स्क्रीन की जरूरत अलग-अलग होती है इसलिए सभी के लिए एक ही समय-सीमा सही नहीं मानी जाएगी। आखिर में तकनीक को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं बल्कि उसका समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। देखा जाता है कि डिजिटल दुनिया से जुड़े रहने के साथ वास्तविक रिश्तों, शारीरिक गतिविधियों और खुद के लिए समय निकालना मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए बेहतर संतुलन बनाने में मदद कर सकता है।स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। जिसमें पढ़ाई से लेकर ऑफिस के काम और दोस्तों से बातचीत तक कई गतिविधियां स्क्रीन के जरिए होती हैं। वहीं अब तकनीक ने जिंदगी को और भी आसान बना दिया लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर डाल सकता है। जिसको देखते हुए सवाल यह है कि क्या हम तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या धीरे-धीरे उसी पर निर्भर होते जा रहे हैं? यदि जीवन में डिजिटल संसार ने ज्ञान का अपार भंडार खोल दिया है तो दूसरी ओर जीवन में सरलता सहजता और अन्तर्मन की खुशी को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। जीवन में बहुत कुछ सीखने पाने हासिल करना उस समय निरर्थक हो जाता है जब भीतर का आह्लाद अनुभव नहीं होता जब पास में मौजूद प्रकृति का सौंदर्य बोध ह्रदय में कोई उमंग नहीं जगाता जब पास मे मौजूद परिजनों से मिलकर बात कर कोई खुशी महसूस नहीं होती जब जीवन के अस्तित्व से जुड़ी अनुभूतियाँ क्षीण होने लगती है। **(लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल**

दीपावली से पहले कर्मचारियों को झटका: डीए और एरियर के आदेश के बाद भी कोषालयों में अटका भुगतान, पोर्टल की विंडो बंद

भोपाल,यशभारत।

मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों के लिए दीपावली का उल्लास फीका पड़ता नजर आ रहा है। शासन के वित्त विभाग द्वारा 30 अक्टूबर को 2 प्रतिशत बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन तकनीकी बाधाओं के चलते यह राहत कागजों से जमीन पर उतरती नहीं दिख रही है। आलम यह है कि आदेश जारी होने के चार दिन बाद भी कोषालयों में भुगतान के लिए देयक नहीं लग पा रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह एरियर पोर्टल पर भुगतान की विंडो का बंद होना है।



10 महीने के एरियर का लाभ, पर प्रक्रिया पर लगा ब्रेक

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने इस पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के आदेश के अनुसार जनवरी से सितंबर तक के 9 महीने के एरियर की पहली किस्त नवंबर में, दूसरी दिसंबर में और तीसरी जनवरी में दी जानी है। चूंकि 30 अक्टूबर को आदेश जारी होने से पहले सितंबर का वेतन मिल चुका था, इसलिए कर्मचारियों को नियमानुसार 10 महीने का एरियर मिलना चाहिए। लेकिन, आईएफएमआईएस पोर्टल की साइट और भुगतान विंडो बंद होने के कारण कोषालय स्तर पर प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।

कर्मचारी संघ की दो टूक: 6 नवंबर तक खुले विंडो-

श्रेणीवार बढ़ेगा वेतन और एरियर का गणित

2% डीए बढ़ने से विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के मासिक वेतनमें यह वृद्धि होगी:
प्रथम श्रेणी: ?2,462 से ?3,000 प्रति माह
द्वितीय श्रेणी: ?1,346 से ?1,600 प्रति माह
तृतीय श्रेणी: ?390 से ?1,200 प्रति माह
चतुर्थ श्रेणी: ?310 से ?400 प्रति माह

वहीं, 10 महीने के कुल एरियर का लगभग एक-तिहाई हिस्सा पहली किस्त के रूप में मिलना है:

प्रथम श्रेणी: कुल ?24,620 से ?30,000
द्वितीय श्रेणी: कुल ?13,460 से ?16,000
तृतीय श्रेणी: कुल ?3,900 से ?12,000
चतुर्थ श्रेणी:कुल ?3,100 से ?4,000

कर्मचारी संगठनों ने दो टूक मांग की है कि दीपावली के पावन पर्व से पहले कर्मचारियों के खातों में पहली किस्त की राशि हर हाल में पहुंचनी चाहिए। संघ ने वित्त विभाग से तत्काल हस्तक्षेप करते हुए प्रदेश के सभी कोषालयों के लिए भुगतान हेतु आईएफएमआईएस की विंडो को तुरंत खुलवाने की मांग की है, ताकि समय रहते देयक प्रस्तुत हो सकें और कर्मचारी इस पर्व को खुशी के साथ मना सकें।



पटाखे चलाते समय आंखों की सुरक्षा का रखें विशेष ध्यान : एम्स भोपाल

दिवाली पर सुरक्षात्मक चश्मा पहनें, आंख में चोट लगने पर तुरंत विशेषज्ञ से लें सलाह

भोपाल ,यश भारत।

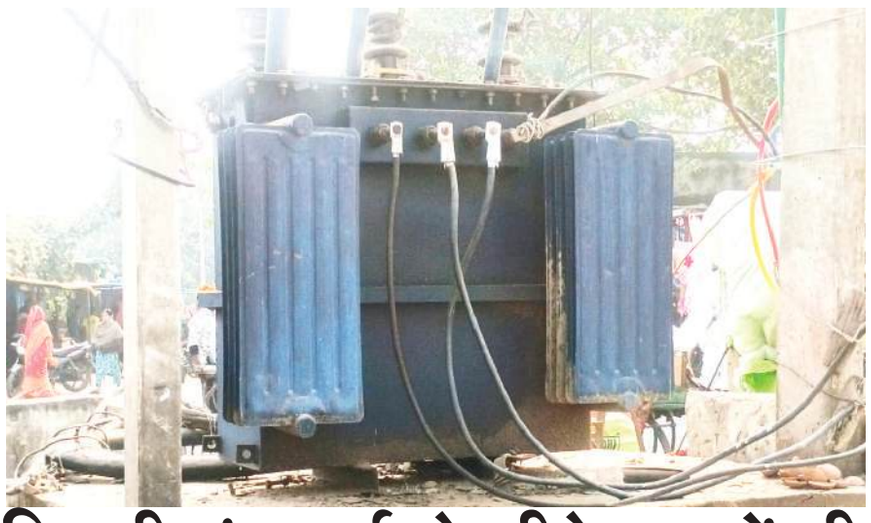
दीपावली पर आतिशबाजी के दौरान थोड़ी सी लापरवाही आंखों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इसे देखते हुए एम्स भोपाल ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर सुरक्षित दिवाली मनाने की अपील की है। एम्स ने पटाखे हमेशा वयस्कों की निगरानी में चलाने और छोटे बच्चों को अकेले आतिशबाजी नहीं करने देने की सलाह दी है। एडवाइजरी के अनुसार पटाखे खुले और सुरक्षित स्थान पर चलाएं तथा आंखों को धुएं, कणों और तेज रोशनी से बचाने के लिए सुरक्षात्मक चश्मा पहनें। पटाखा जलाने के बाद तुरंत सुरक्षित दूरी पर चले जाएं। अधजले पटाखों को दोबारा जलाने या छूने से बचें। पास में पानी की बाल्टी भी रखें। एम्स ने बताया कि आंख में चोट लगने पर उसे रगड़ें नहीं। धूल या कण जाने पर साफ पानी से धीरे धीरे धोएं। तेज दर्द, खून आने या धुंधला दिखाई देने पर तत्काल अस्पताल अथवा नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें। बिना विशेषज्ञ की सलाह के घरेलू उपचार न करें।

निर्मला सप्रे की सदस्यता पर दो महीने में फैसला करे विधानसभा अध्यक्ष : सुप्रीम कोर्ट

भोपाल, यश भारत। बीना विधायक निर्मला सप्रे के दल-बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर निर्णय लेने को कहा है। यह याचिका विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर दायर की थी। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने अदालत में पक्ष रखा। दरअसल निर्मला सप्रे ने वर्ष 2023 में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता था। बाद में उनके भाजपा में शामिल होने का मामला सामने आया। इस पर सिंघार ने दल-बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सिंघार ने कहा कि जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सप्रे को चुनकर विधानसभा भेजा था। दल बदल के मामले में जनता के जनादेश की गरिमा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित समय सीमा में निष्पक्ष और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप निर्णय लेंगे।







बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे पटाखों की दुकान लगाई तो हो सकती है कार्रवाई

दीपावली पर विद्युत सुरक्षा को लेकर बिजली कंपनी की एडवाइजरी

भोपाल, यश भारत।

दीपावली पर विद्युत दुर्घटनाओं से बचाव के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल सहित 16 जिलों के उपभोक्ताओं और व्यापारियों से सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने पटाखा व्यापारियों को बिजली की लाइनों के नीचे ट्रांसफार्मर के नीचे या उनसे सटाकर दुकान नहीं लगाने की हिदायत दी है। बिजली लाइनों के आसपास आतिशबाजी और पटाखों का प्रदर्शन नहीं करने को भी कहा है। कंपनी ने मिठाई मूर्ति सजावटी सामान और पटाखों की अस्थाई दुकानों में रोशनी के लिए नियमानुसार अस्थाई बिजली कनेक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। स्वीकृत भार से अधिक बिजली उपयोग और सीधे तार डालकर कनेक्शन लेने पर रोक लगाई गई है। कंपनी का मैदानी अमला और सतर्कता विंग बिजली चोरी की जांच करेगा। अनियमितता मिलने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली के प्रदर्शन में नहीं पहुंचे तो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई का आरोप

भोपाल,यश भारत। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित प्रदर्शन में शामिल नहीं होने पर मध्यप्रदेश के कुछ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठन से हटाए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रदर्शन में अनुपस्थित रहने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पदों से हटा दिया गया है। इस कार्रवाई को लेकर एक प्रभावित कार्यकर्ता ने नाराजगी जताई है। उसका कहना है कि पारिवारिक शोक के कारण वह दिल्ली के प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सका था। इसके बावजूद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्यकर्ता ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। मामले के सामने आने के बाद यूथ कांग्रेस की संगठनात्मक कार्यप्रणाली और कार्यकर्ताओं के प्रति जवाबदेही को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि अब तक संबंधित पदाधिकारियों की ओर से कार्रवाई के कारणों और आरोपों पर आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।



इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों को मिलेगा कस्टम्स और जीएसटी का मार्गदर्शन



रिटायर्ड IRS अधिकारी देंगे टैरिफ और व्यापार नीतियों की जानकारी

मुंबई, यश भारत। इलेक्ट्रॉनिक्स आयात और निर्यात कारोबार को आसान बनाने के उद्देश्य से ऑल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (AIE) वेस्ट ज़ोन ने ट्रेड ब्रिज एडवाइज़र्स LLP (TBA) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत TBA को कस्टम्स, जीएसटी और विदेश व्यापार नीति के मामलों में एसोसिएशन का नॉलेज एवं एडवाइजरी पार्टनर बनाया गया है।समझौते पर U AIEA की ओर से राष्ट्रीय महासचिव मितेश मोदी और अध्यक्ष मनोज अडवानी ने हस्ताक्षर किए। वहीं ट्रेड ब्रिज एडवाइज़र्स की ओर से फाउंडिंग पार्टनर एवं रिटायर्ड ढ्ढ्रू अधिकारी आरके जैन तथा एसोसिएट पार्टनर राजीव मागू ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों को आयात-निर्यात शुल्क, टैरिफ में बदलाव, मुक्त व्यापार समझौतों (FTA), जीएसटी और सरकार की नई व्यापार योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। रिटायर्ड IRS अधिकारियों का अनुभव कारोबारियों को नियमों और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा।ITBA सदस्यों की व्यापार संबंधी समस्याओं को संबंधित सरकारी विभागों के सामने उठाने, नीतिगत सुझाव देने और उनके समाधान में सहयोग करेगा। इसके अलावा हर तिमाही सेमिनार, संवाद सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। नए सरकारी नोटिफिकेशन और व्यापार नीतियों में बदलाव की जानकारी भी समय पर उपलब्ध कराई जाएगी।↓IEA महासचिव मितेश मोदी ने कहा कि बदलते व्यापार नियमों के बीच सदस्यों को भरोसेमंद मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं आरके जैन ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य सरकारी नीतियों और व्यापारियों के बीच की दूरी कम करना तथा कारोबार को सुगम बनाना है।

जबलपुर के झालर बाजार में इस बार 'मेड इन इंडिया' का दबदबा: चाइनीज लाइटिंग से कड़ी टक्कर



यश भारत , जबलपुर। रोशनी के महापर्व दीपावली को लेकर संस्कारधानी जबलपुर के इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में जबर्दस्त रौनक छाई हुई है। शहर के मुख्य व्यापारिक केंद्रों–जैसे फुहारा, लार्डगंज, गढ़ा बाजार और बड़ा फुहारा की दुकानों पर रंग-बिरंगी झालरों और सजावटी लाइट्स की खरीदारी के लिए ग्राहकों का हुजूम उमड़ रहा है। इस बार जबलपुर के बाजार में 'मेड इन इंडिया' और 'चाइनीज' लाइटिंग के बीच सीधा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है।

स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक कारोबारियों के अनुसार, पिछले सालों की तुलना में इस बार जबलपुर के ग्राहकों की सोच और पसंद में बड़ा बदलाव आया है। चीनी सामान की मोनोपोली खत्म हो रही है और स्वदेशी उत्पादों की तरफग्राहकों का रुझान तेजी से बढ़ा है।

बाजार का गणित: चाइनीज बनाम मेड इन इंडिया झालर

(एक तुलनात्मक विश्लेषण)

विशेषता	चाइनीज झालर	मेड इन इंडिया झालर
1. (कीमत)	30% से 50% तक सस्ती	चाइनीज से थोड़ी महंगी
2. (वायर क्वालिटी)	पतला एल्युमीनियम/ मिक्स वायर	मोटा शुद्ध कॉपर वायर
3. (लाइफ)	1 सीजन (सिंगल यूज़)	3 से 5 साल (रिपेयर योग्य)
4. (जबलपुर में शेयर)	50% (बजट सेगमेंट)	50% (क्वालिटी व सुरक्षा सेगमेंट)

बाजार की मुख्य स्थितियां

कीमत-टिकाऊपन: चाइनीज झालरें अपनी कम कीमत और नित-नए फैंसी डिज़ाइनों के कारण बजट ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई हैं। वहीं, भारतीय झालरें अपने मोटे कॉपर वायर और लॉन्ग-लाइफ के दम पर पकड़ बना चुकी हैं।

सुरक्षा-री-यूज़ेबिलिटी: चीनी झालरों में पतले वायर का इस्तेमाल होने से शॉर्ट-सर्किट का जोखिम अधिक रहता है और खराब होने पर इन्हें सुधारा नहीं जा सकता। दूसरी ओर, मेड इन इंडिया झालरें पूरी तरह सुरक्षित हैं।

स्थानीय मांग के अनुसार सप्लाई: जबलपुर के थोक व्यापारी इस बार दिल्ली के भागीरथ पैलेस और गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग हब्स से भारी मात्रा में स्वदेशी और हाई-क्वालिटी असेंबल झालरें मंगवा रहे हैं।

14 साल से पदोन्नति का इंतजार, मेडिकल कॉलेज प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम

जबलपुर,यशभारत।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति का मामला एक बार फिर गरमा गया है। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संघ ने कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिलाने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। संघ ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर, लिपिक वर्ग, टेक्नीशियन एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पिछले लगभग 14 वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य शासन के निर्देशों के बावजूद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पदोन्नति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है, जबकि प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में नियमानुसार पदोन्नति की



कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक सेवा देने के बाद भी कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। संघ ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से सभी पात्र कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर उन्हें नियमानुसार लाभ प्रदान करने की मांग की है। यदि आगामी 10 दिनों में पदोन्नति संबंधी कार्यवाही शुरू नहीं की गई तो संघ कर्मचारियों के हित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।



महाकोशल कॉलेज में दिव्यांगों के साथ मनाया दीपोत्सव

जबलपुर. प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय महाकोशल महाविद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ खुशियां बांटकर पंचमहोत्सव पर्व का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रो. अरुण शुक्ल द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को मिठाई एवं वस्त्र भेंट किए गए। उपहार पाकर विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी और उत्साह झलक उठा। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच आत्मीयता, अपनत्व और खुशियां साझा करने का संदेश देना रहा। कार्यक्रम के दौरान डॉ. राजीव मिश्रा, डॉ. महेंद्र कुशवाहा, डॉ. तरुणेंद्र साकेत एवं मनीष रघुवंशी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

अनियंत्रित होकर पलटी ऑटो रिक्शा में फंसे यात्रियों को निकाला बाहर, घायलों को पहुंचाया अस्पताल

हादसे के मददगार बने कलेक्टर

जबलपुर। बिलहरी क्षेत्र में डीमार्ट के पास सवारियों से भरी एक ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सवार यात्री ऑटो रिक्शा में फंस गए और कुछ यात्री उसके नीचे दब गए। इसी दौरान वहां से गुजर रहे कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने तत्काल अपना वाहन रुकवाया और घटना स्थल पर पहुंचकर ऑटो रिक्शा में सवार यात्रियों को बचाने में मदद की। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने मौके पर मौजूद लोगों के साथ मिलकर पलटी हुई ऑटो को सीधा कराया और उसमें फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्होंने हादसे में घायल यात्रियों को पीछे से आ रही खनिज विभाग के वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया।



कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी को मौके से फोन कर घायलों का समुचित एवं त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। ऑटो रिक्शा में तीन महिलाएं, एक बच्चा, एक पुरुष और चालक सहित कुल छह लोग सवार थे।इनमें एक बच्चा और एक महिला सहित चार व्यक्तियों को घायल होने पर खनिज विभाग के वाहन से जिला अस्पताल भेजा गया।

प्लेटफार्म पर मिला अज्ञात वृद्ध का शव

जीआरपी जांच में जुटी

जबलपुर यशभारत। मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर एक अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर जीआरपी थाना जबलपुर की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वृद्ध की मृत्यु अज्ञात बीमारी के चलते होना बताई जा रही है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच और चिकित्सकीय परीक्षण के बाद ही चल सकेगा। जीआरपी के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 60 वर्ष है। उसका रंग सांवला, कद करीब 5 फीट 2 इंच और शरीर इकहरा है। मृतक ने स्लेटी रंग की टी-शर्ट और काले रंग का लोअर पहन रखा था। उसकी सफेद दाढ़ी-मूंछ और सिर पर सफेद बाल हैं।

एनएच-30 पर सड़क हादसे अज्ञात अधेड़ की मौत

मृतक की पहचान के लिए पुलिस ने शुरू किए प्रयास

जबलपुर यशभारत। जिले के पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर हुए सड़क हादसे में करीब 65 से 70 वर्षीय एक अज्ञात अधेड़ की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार एनएच-30 पर अज्ञात परिस्थितियों में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए बुजुर्ग को गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पनागर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक की उम्र लगभग 65 से 70 वर्ष के बीच बताई जा रही है। फिलहाल उसके पास से ऐसा कोई दस्तावेज या जानकारी नहीं मिल सकी है, जिससे उसकी पहचान हो सके।

केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रही हैं : बंशीलाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है

यश भारत



रायपुर। किसान मोर्चा की प्रदेश इकाई द्वारा किसान मितान योजना के नवीन प्रयोग को संगठन के विस्तार की दृष्टि से सराहनीय प्रयोग बताते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मोर्चा प्रत्येक मतदान केंद्र (बूथ) तक 10-10 कार्यकर्ताओं को जोड़कर संगठन को मजबूत कर रहा है। गुर्जर ने कहा कि यह मितान (मित्र/दोस्त) ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे। किसानों की वास्तविक समस्याओं व धरातल की हकीकत को सरकार तक पहुँचाने की जिम्मेदारी इन मितानों की होगी, जिससे सरकार त्वरित मदद कर सके।

गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में लगभग 82 प्रतिशत छोटे किसान हैं जो बेहद मेहनती हैं। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में ?3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का जो वादा किया था, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश का भाजपा सरकार उसे पूरी पारदर्शिता के साथ धरातल पर उतार रही है। राज्य में 3100 से अधिक धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। किसानों की एक यूनिक आईडी बनाई गई है, जिससे उन्हें बार-बार पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। डिजिटल सर्वे और बोए गए रकबे के आधार पर पारदर्शी तरीके से धान खरीदी जारी है। श्री गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को आदान सहायता के रूप में तीन वर्षों में लगभग 35 हजार करोड़ रुपये देने का कार्य किया है, जिससे प्रदेश के किसान सशक्त हुए हैं। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुर्जर ने बताया कि धान की फसल छोड़कर दलहन या अन्य वैकल्पिक फसलों को अपनाने और उत्पादन करने वाले किसानों को राज्य सरकार द्वारा 15 हजार रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए श्री गुर्जर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। केंद्र सरकार की योजनाओं और जीडीपी में किसानों की हिस्सेदारी की चर्चा करते हुए श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगुनी करने की दिशा में लगातार कार्य हो रहा है। पहले जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 13.75 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के आसपास हुआ करती थी, जो अब केंद्र सरकार के प्रयासों के चलते बढ़कर 17 प्रतिशत से 18 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच रही है। प्राकृतिक आपदाओं और जोखिमों से किसानों को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और बेहतर रिस्क मैनेजमेंट मॉडल को छत्तीसगढ़ में प्रभावी रूप से लागू किया गया है। संकट की हर घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रही हैं। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में कृषि ऋण पर 16 प्रतिशत ब्याज दर को चरणबद्ध तरीके से घटाकर शून्य प्रतिशत किया गया था। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय दुगुनी करने और उन्हें सीधा लाभ पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। श्री ठाकुर ने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में हर निर्णय में किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ठाकुर ने बताया कि सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों को गाँव, खलिहान और प्रत्येक किसान तक पहुँचाने के उद्देश्य से किसान मितान का गठन किया जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत किसानों की नीतिगत समस्याओं को संगठन के माध्यम से सत्ता और सम्बन्धित उचित मंच तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनका समय पर समाधान हो सके। भाजपा किसान मोर्चा मंडलों के गठन के बाद अब मतदान केंद्र (पोलिंग बूथ) स्तर तक अपने संगठन का विस्तार कर रहा है। पत्रकार वार्ता में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. शंभू, किसान मोर्चा के छत्तीसगढ़ प्रभारी व राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, पूर्व विधायक व किसान मोर्चा ओड़िशा प्रभारी पिंकी शिवराज शाह तथा छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के प्रभारी पूनम चंद्राकर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे

धनतेरस से पहले बी एस पी मैकेनिकल आर्गेनाइजेशन के 466 कर्मचारियों को गिफ्ट मिलना शुरू



भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के मैकेनिक ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों को नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन स्कीम के तहत एक समारोह में सीजीएम इंचार्ज (एमएंडयू) बिजय कुमार बेहरा द्वारा बिल्डिंग नंबर 2 के एम एंड यू सभागार में गिफ्ट वितरित किया गया।

भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा कर्मचारी एवं अधिकारियों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के लिए इस वर्ष मार्च महीने में नान फाइनेंशियल मोटिवेशन स्कीम शुरू किया गया। इस स्कीम के तहत मिली राशि का गिफ्ट खरीदने के लिए मुख्य महाप्रबंधक (मैकेनिक) ने जी एम इंचार्ज सुनील कुमार के नेतृत्व में एक कमेटी गठित किया, जिसने निर्णय लिया कि सेलम स्टील प्लांट से गिफ्ट खरीदा जाएगा।

गिफ्ट वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीजीएम इंचार्ज एम एंड यू बी के बेहरा ने कर्मचारियो एवं अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रबंधन की पूरी मंशा रहती है कि वह अपने कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखें। इसी कड़ी में यह स्कीम शुरू की गई थी। निश्चित ही इसका सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। हमारा प्रयास रहेगा की कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए आगे भी आगे भी कई कदम उठाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में सेल का अर्धवार्षिक टैक्स पूर्व लाभ 4516 करोड़ रुपया है, जो कि एक सुखद संकेत है। इसी तरह यदि हम पूरे मनोबल के साथ काम करते रहेंगे तो निश्चित ही सेल चेयरमैन अशोक कुमार पंडा द्वारा दिए गए 10000 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अवार्ड पाने वाले सभी कर्मचारियों अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

महाप्रबंधक प्रभारी (मैकेनिकल) बीडी बाबू ने अपने संबोधन में कहा कि मैकेनिकल आर्गेनाइजेशन के सभी विभाग बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। इस तरह की स्कीम से निश्चित ही कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है।

कन्हैया सोनी ने किया खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन



भिलाई। बी जे पी नेता कन्हैया सोनी ने भिलाई के शांति नगर दशहरा मैदान में आयोजित बॉलीवाल प्रतियोगीता मे अतिथि के रूप मे शामिल होकर भिलाई के प्रतिभाशाली वॉलीबॉल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन एवं प्रोत्साहित किया।

इस अवसर पर श्री सोनी ने सभी खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने तथा अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भिलाई का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षकगण, पालकगण एवं बच्चों का उत्साह सराहनीय रहा। उन्होंने कहा की मैं भिलाई की पूरी वॉलीबॉल टीम के सभी खिलाड़ियों को उनके उज्वल भविष्य एवं बेहतर प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। आप सभी इसी तरह मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहें और भिलाई का गौरव बढ़ाते रहें। भिलाई के खिलाड़ियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ!

जशपुर में 11 से 18 तक मनेगा जनजातीय गौरव सप्ताह, करमा महोत्सव और जनजातीय स्वाभिमान सम्मेलन होंगे मुख्य आकर्षण

जशपुरनगर। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जशपुर जिले में 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जाएगा। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार आयोजित इस सप्ताह में विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सम्मान समारोहों के माध्यम से जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को रेखांकित किया जाएगा। आदिम जाति कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कार्यक्रमों की शुरुआत 10 नवंबर को पत्रकारवार्ता से होगी। इसके बाद 11 नवंबर को पंडित रामचन्द्र पौराणिक सामुदायिक भवन, बालाजी मंदिर के सामने जशपुर में जिला स्तरीय उत्तर छत्तीसगढ़ क्षेत्र जनजातीय लोकनृत्य महोत्सव, करमा महोत्सव एवं शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव के तहत नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 13 नवंबर को जिले के सभी ग्रामों, ग्राम पंचायतों, विकासखंडों और नगरीय निकायों में जनजातीय एवं अन्य महापुरुषों की प्रतिमाओं और स्मारक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलन भी किया जाएगा। 15 नवंबर को पंडित रामचन्द्र पौराणिक सामुदायिक भवन में मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसमें जनजातीय क्रांतियों के नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों तथा प्रमुख जनजाति एवं उपजनजाति प्रमुखों का सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर जनजातीय स्वाभिमान सम्मेलन, कला एवं संस्कृति प्रदर्शनी, फोटोग्राफी और चित्रकला प्रतियोगिता के साथ पुरस्कार वितरण समारोह भी होगा। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन किया जाएगा। 16 नवंबर को जिला पुरातत्व संग्रहालय जशपुर में जनजातीय विकास प्रदर्शनी के साथ क्राफ्ट, कला, शिल्प, पारंपरिक व्यंजन और पुस्तक मेले का आयोजन होगा। इसमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक जनजातीय वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।वहीं, 18 नवंबर को जिला पंचायत सभाकक्ष में जनजातीय कला, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण विषय पर प्रशिक्षण, कार्यशाला, संगोष्ठी एवं सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन होगा। पूरे सप्ताह जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।

तीन दिन में दो मुख्य प्रमोटरों पर शिकंजा कसने से कांग्रेस का सट्टा सिंडिकेट बेनकाब : भाजपा

प्रवक्ता चौधरी बोले महादेव सट्टा एप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल की बौखलाहट उजागर

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में केंद्रीय जाँच एजेंसियों की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तीन दिन के भीतर महादेव सट्टा एप के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के प्रत्यर्पण और अब सह-प्रमोटर रवि उप्पल की दुबई में गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी भी भ्रष्टाचारी या आर्थिक अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

चौधरी ने कहा कि महादेव सट्टा एप घोटाले की एफआईआर में भूपेश बघेल स्वयं छठे नंबर पर नामजद आरोपी हैं। जो व्यक्ति खुद हजारों करोड़ रुपये के संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के इस काले कारोबार में संदिग्ध और आरोपी के रूप में जाँच के दायरे में है, वह आज जाँच एजेंसियों की निष्पक्ष प्रक्रिया पर सवाल उठाने का दुस्साहस कर रहा है। चोर मचाए शोर की तर्ज पर बघेल जनता का ध्यान भटकाने के लिए मनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं। श्री चौधरी ने लुकआउट सर्कुलर को लेकर बघेल द्वारा उठाए जा रहे सवालों को

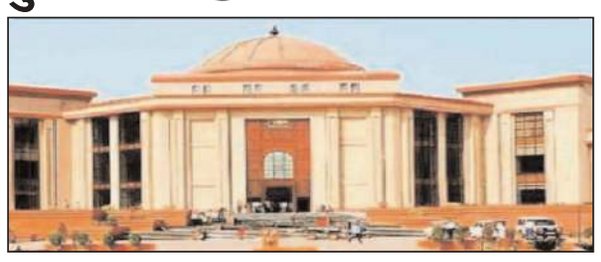


उनकी प्रशासनिक अज्ञानता और हताशा का परिचायक बताया और कहा कि लुकआउट नोटिस तब जारी किया जाता है जब किसी आरोपी के अपराध करने के बाद देश छोड़कर विदेश भागने की आशंका होती है। बघेल यह भूल रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, तब उनके संरक्षण और प्रशासनिक शिथिलता के चलते ही इस सट्टा एप के सरगना आराम से देश छोड़कर विदेश भागने में सफल रहे थे। जो आरोपी पहले ही देश से बाहर भाग चुके थे, उनके लिए अब लुकआउट नोटिस जारी करने की मांग करना बघेल के राजनीतिक पाखण्ड और कानूनी समझ के खोखलेपन को उजागर करता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पाँच वर्षों के कुशासन में छत्तीसगढ़ को सट्टेबाजों और हवाला कारोबारियों की सुरक्षित शरणस्थली बना दिया गया था। नौकरशाहों और राजनेताओं तक करोड़ों रुपये का अवैध कमीशन पहुँचाया जाता था। अब जब सीबीआई और ईडी जैसी केन्द्रीय जाँच एजेंसियाँ विदेश में बैठे मुख्य सिंडिकेट ऑपरेटरों को एक-एक कर कानून के शिकंजे में ला रही हैं, तब कांग्रेस और भूपेश बघेल की जमीन खिसक चुकी है। श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार कानून के राज और पारदर्शी जाँच के लिए प्रतिबद्ध है। महादेव सट्टा एप के जरिए प्रदेश और देश के युवाओं को बर्बाद करने वाले किसी भी दोषी को, चाहे वह दुबई में बैठा प्रमोटर हो या रायपुर में बैठा उनका राजनीतिक संरक्षक, कानून के कठघरे में खड़ा होकर अपने कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा।

घरौंदा केंद्रों की बदहाल व्यवस्था उजागर

बिलासपुर में दिव्यांग को बांधकर रखने का आरोप; रायपुर में 4 महिलाओं की मौत



बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मानसिक रूप से अस्वस्थ और विशेष देखभाल की जरूरत वाले लोगों के लिए संचालित घरौंदा केंद्रों की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बिलासपुर के एक केंद्र में दिव्यांग व्यक्ति को पलंग से बांधकर रखने का मामला सामने आया है। वहीं, रायपुर के घरौंदा केंद्र में एक बच्चे समेत चार महिलाओं की मौत का खुलासा हुआ है। कोर्ट कमिश्नरों की निरीक्षण रिपोर्ट में सामने आई इन स्थितियों पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

बच्चों की मौत और लापता होने का मामला पहले से विचाराधीन

दरअसल, रायपुर के घरौंदा केंद्र में आठ बच्चों की मौत और पांच बच्चों के लापता होने का मामला पहले ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के संज्ञान में आ चुका है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इन घटनाओं को अमानवीय बताते हुए सभी कोर्ट कमिश्नरों को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने 11 कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति की थी। इनमें एडवोकेट विवेक श्रीवास्तव, अपूर्व त्रिपाठी, संघर्ष पाण्डेय, शिवाली दुबे और ईश्वर जायसवाल सहित अन्य शामिल हैं। कमिश्नरों ने शासन और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत संचालित घरौंदा केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की वास्तविक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की है।

इससे पहले वित्त विभाग और समाज कल्याण विभाग के सचिवों के साथ मुख्य सचिव ने भी हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया था। इसमें बताया गया था कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने इन केंद्रों में रहने वाले बच्चों पर करीब 9 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हालांकि, निरीक्षण रिपोर्ट में सामने आई स्थितियों ने सरकारी व्यवस्था और देखरेख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस पूरे मामले की शुरुआत रायपुर की संस्था कोपलवाणी की ओर से दायर जनहित याचिका से हुई। याचिका में वर्ष 2014 से संचालित घरौंदा केंद्र में बच्चों की देखरेख और कथित भूखमरी से मौत के मामलों को उठाया गया था। संस्था ने पहले भी राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी।

अब कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई में सरकार के जवाब और केंद्रों की व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए गए कदमों पर सबकी नजर रहेगी।

प्रधानमंत्री आवास के नाम पर वसूली का आरोप, रोजगार सहायिका और पति पर 20 हजार तक लेने की शिकायत



महासमुंद । छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बागबाहरा विकासखंड के ग्राम कोमा के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की रोजगार सहायिका और उनके पति पर आवास स्वीकृत कराने के बदले हितग्राहियों से 3 हजार से 20 हजार रुपये तक वसूलने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने शपथ पत्रों के साथ कलेक्टर से शिकायत कर रोजगार सहायिका को पद से हटाने और मामले में कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों के मुताबिक, रोजगार सहायिका और उनके पति ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाने का भरोसा देकर अलग-अलग लोगों से 3 हजार, 5 हजार, 10 हजार और 20 हजार रुपये तक लिए हैं। शिकायत को मजबूत आधार देने के लिए ग्रामीणों ने 10 रुपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए हैं।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि रकम देने के बावजूद उनके नाम पर अब तक आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं। जब वे अपनी दी गई राशि वापस मांगते हैं तो कथित तौर पर उन्हें टाल दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले भी इस संबंध में शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें दोबारा कलेक्ट्रेट पहुंचना पड़ा।

कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही आरोपों की पुष्टि होने पर संबंधित रोजगार सहायिका को पद से हटाने और दोषियों के खिलाफसख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई है।

मामले में जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि जनपद पंचायत से इस प्रकरण की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित रोजगार सहायिका को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। उनके जवाब और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कथित वसूली के इन आरोपों से पंचायत स्तर पर योजना के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब जांच के नतीजों पर नजर रहेगी कि ग्रामीणों की शिकायत में कितनी सच्चाई सामने आती है और प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है।

राज्य वित्त सेवा संवर्ग के 27 लेखित अधिकारियों का तबादला

रायपुर। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के 27 लेखित अधिकारियों जिनमें दो संयुक्त संचालक शामिल है का तबादला आदेश कल जारी किया गया। विवेक कुमार मिश्रा, संयुक्त संचालक कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, दुर्ग से संयुक्त संचालक, संचालनालय कोष एवं लेखा, नवा रायपुर अटल नगर, अभिषेक शर्मा, संयुक्त संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा, नवा रायपुर अटल नगर से संयुक्त संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन दुर्ग, श्रीमती योगेश्वरी डेंजारे, वरिष्ठ लेखाधिकारी जिला पंचायत, बिलासपुर से , उप संचालक (वित्त), कार्यालय आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर, सुश्री अंकिता सिंह, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, अंबिकापुर से उप संचालक (वित्त), छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कार्पोरेशन लिमेटेड, रायपुर, विनोद कुमार उपगड़े, उप संचालक (वित्त), छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग नवा रायपुर अटल नगर से वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जशपुर, विजय कुमार वर्मा, उप संचालक (वित्त). कार्यालय आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर से वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत, बिलासपुर, चंद्रशेखर सराफ, उप संचालक (वित्त), प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग रायपुर एवं अतिरिक्त प्रभार उप संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर से वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, कोरिया अतिरिक्त प्रभार लेखाधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया, जिला-कोरिया, अनिल कुमार तिन्हा, उप संचालक, (वित्त), संचालनालय, मछली पालन इंद्रायली भवन, नवा रायपुर अटल नगर से वित्त अधिकारी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर (वरिष्ठ पद के विरुद्ध), जयकुमार सिंह, लेखाधिकारी, शासकीय इंजीनियरिंग, महाविद्यालय, बिलासपुर से सहायक संचालक (वित्त), संचालनालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छत्तीसगढ़, नया रायपुर अटल नगर (वरिष्ठ पद के विरुद्ध), सुश्री कंचन पूआर्य, कोषालय अधिकारी चौकी जिला कोषालय, मोहला मानपुर-अंबागढ़ से लेखाधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, रायपुर मुख्यालय छत्तीसगढ़, टेकेन्द्र कुनार, प्रशासकीय अधिकारी आंतकीय चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव से लेखाधिकारी, जिला पंचायत, सुकमा एवं अतिरिक्त प्रभार लेखाधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अतिरिक्त परियोजना क्रियान्वयन इकाई सुकमा - 2, सुश्री ऋद्धि साहू, लेखाधिकारी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिला क्रियान्वयन इकाई, रायगढ़-। से लेखाधिकारी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, परियोजनांग्रामीण विकास, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, लोकेन्द्र कुमार साहू, विशेष अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय, भवन, नवा रायपुर अटल नगर से लेखाधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कर्तव्यस्योजना, जिल्ला परियोजना क्रियान्ययन महानदीइकाई कांकेर। (लेखाधिकारी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई-1 कांकेर), आशीष एक्का,



लेखाधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर से सहायक संचालक, कार्यर्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अंबिकापुर, पद्माकर सिंह परिहार, वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, कोरिया से लेखाधिकारी, राज्य ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, नवा रायपुर अटल नगर, रमाकांत राय, लेखाधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया से कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, अंबिकापुर (वरिष्ठ पद के विरुद्ध), शशि दुबे, सहायक संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन, दुर्ग से लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सान्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, चंद्रकांत केवट, कोषालय जिला कोषालय जशपुर से (वरिष्ठ अधिकारी सहायक संचालक (वित्त), छत्तीसगढ़ लोक पद के सेवा आयोग, नया रायपुर अटल नगर (वरिष्ठ पद के विरुद्ध), राजेश कुमार लहरे, लेखाधिकारी, राज्य ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, नया रायपुर अटल नगर से लेखाधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बिलासपुर-।, श्रीमती मधुलिका डिल्सेना, लेखाधिकारी, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रायपुर से प्रशासकीय अधिकारी, शासकीय चिकित्ता महाविद्यालय, कोरबा, किरण कुमार, सहायक संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा, नवा रायपुर अटल नगर से कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, मोडला-मानपुर - अंबागढ़ चौकी, धनीराम खरे, सहायक संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, जगदलपुर से लेखाधिकारी, ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई, नवा रायपुर अटल नगर, चंदन टंडन, लेखाधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी से सहायक संचालक, कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, राजेंद्र कुमार बंजारे, लेखाधिकारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, रायपुर मुख्यालय छत्तीसगढ़ से कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय नारायणपुर, संजय कुमार धीवर, सहायक संचालक कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अंबिकापुर से सहायक संचालक, कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल, श्रीमती सैल ध्रुव, लेखाधिकारी, ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई, नवा रायपुरसे लेखाधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी तथा एलेश कुमार साहू, सहायक संचालक, कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक छत्तीसगढ़ नया रायपुर अटल नगर से लेखाधिकारी, ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इनाई दुर्ग, संभाग दुर्ग में पदस्थ किए गए है।

अमेरिकी क्रिकेट को दिवालियापन से निकालने की शुरू हुई तैयारी



न्यूयार्क, एजेंसी। अमेरिका क्रिकेट को दिवालियापन से बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। कोर्ट नियुक्त ट्रस्टी मार्क डेनिस ने बोर्ड के लिए तीन स्वतंत्र डायरेक्टर के नाम प्रस्तावित किए हैं। इनमें सेलिना कैंग, पैट्रिक सिंगलटन और नॉर्मन वेन शामिल हैं।

नई टीम ICC से निलंबित सदस्यता बहाल कराने और अमेरिकी क्रिकेट में प्रशासनिक स्थिरता लाने की जिम्मेदारी संभालेगी। यह प्रस्ताव USA क्रिकेट के रिऑर्गेनाइजेशन प्लान का हिस्सा है, जिसे अमेरिकी बैंकरप्सी कोर्ट में दाखिल किया गया है। मेजर लीग क्रिकेट (MLC) की मालिक कंपनी अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइजेज (ACE) ने भी संगठन को चलाने के लिए 29 करोड़ 68 लाख रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग देने का भरोसा दिया है।

जनवरी 2027 में कोर्ट की मंजूरी मिलने की उम्मीद

कोर्ट नियुक्त ट्रस्टी मार्क डेनिस ने 15 जनवरी 2027 के आसपास रिऑर्गेनाइजेशन प्लान की सुनवाई कराने का अनुरोध किया है। यह सुनवाई अधिकतम 22 जनवरी तक हो सकती है। फंडिंग व्यवस्था के लिए 29 जनवरी तक कोर्ट की मंजूरी जरूरी है। प्लान को मंजूरी मिलने और सभी शर्तें पूरी होने के बाद तीनों नए डायरेक्टर पद संभाल सकते हैं। उसी समय USA क्रिकेट के मौजूदा बोर्ड के सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नए डायरेक्टर के चयन की प्रक्रिया पर ICC और अमेरिकी ओलिंपिक एवं पैरालिंपिक समिति (USOPC) ने भी नजर रखी है।

दरअसल, USA क्रिकेट और ट्रस्ट के बीच लंबे समय से कमर्शियल समझौते को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष 2019 के शुरुआती समझौते की शर्तों के अनुरूप नया करार नहीं कर पाए थे। इसी मतभेद ने संगठन के प्रशासनिक संकट को और बढ़ाया। अब नए बोर्ड को ACE के साथ मिलकर ऐसा समझौता करना होगा, जो ICC की पहले उठाई गई आपत्तियों को भी दूर करे।

ICC सस्पेंशन के दौरान भी जारी रहेगी फंडिंग- USA क्रिकेट की ICC सदस्यता सितंबर 2025 से निलंबित है। इस कारण संगठन को ICC से फंडिंग नहीं मिल रही। ACE की रकम जुलाई में हुए पुराने सेटलमेंट के तहत तय फंडिंग के अतिरिक्त होगी। इसका इस्तेमाल संगठन के रोजमर्रा के खर्च और कामकाज के लिए किया जाएगा।

विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के नए सीजन का रोमांच 14 जनवरी से

पहले मुकाबले में भिड़ेंगी बेंगलुरु और मुंबई

मुंबई, यशभारत। विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के नए सीजन का रोमांच 14 जनवरी से शुरू होगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला शाम 7.30 बजे शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए वडोदरा और मुंबई को मेजबानी की जिम्मेदारी दी है।

टूर्नामेंट के शुरुआती 11 मुकाबले 14 से 24 जनवरी तक वडोदरा में खेले जाएंगे। इसके बाद 26 जनवरी से मुंबई में लीग के शेष मुकाबले आयोजित होंगे। लीग चरण का आखिरी मैच 3 फरवरी को दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। इसके बाद 5 फरवरी को एलिमिनेटर और 7 फरवरी को फाइनल मुकाबला होगा। इस तरह 25 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में खिताब के लिए पांच टीमों के बीच मुकाबला होगा।



पांच टीमें खेलेंगी 22 मुकाबले

डब्ल्यूपीएल में पांच टीमें हिस्सा लेंगी। लीग चरण में प्रत्येक टीम दूसरी चार टीमों के साथ दो-दो मुकाबले खेलेगी। इस तरह लीग चरण में कुल 20 मैच होंगे। इसके बाद एलिमिनेटर और फाइनल सहित टूर्नामेंट में कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी टीमों के बीच लीग चरण में बेहतर प्रदर्शन कर फाइनल तक पहुंचने की होड़ रहेगी।

दोनों चैंपियन टीमों के बीच फिर टक्कर

आरसीबी और मुंबई इंडियंस दोनों ही दो-दो बार डब्ल्यूपीएल का खिताब जीत चुकी हैं। आरसीबी ने 2024 और 2026 में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, जबकि मुंबई इंडियंस भी दो बार खिताब अपने नाम कर चुकी है। दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला 26 जनवरी को मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में खेला जाएगा। पहले ही मैच में इन दोनों मजबूत टीमों की भिड़ंत से टूर्नामेंट को शानदार शुरुआत मिलने की उम्मीद है।

यूपी वॉरियर्स और दिल्ली का अभियान

यूपी वॉरियर्स अपने अभियान की शुरुआत 15 जनवरी को गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले से करेगी। हालिया नीलामी में यूपी वॉरियर्स ने कई बड़े खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम को मजबूत किया है। फ्रेंचाइजी ने ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिन्यू को 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि ग्रेस हैरिस को भी टीम में वापस शामिल किया है। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला मुकाबला 16 जनवरी को आरसीबी के खिलाफ खेलेगी। दिल्ली की टीम अब तक चार बार फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन खिताब जीतने में नाकाम रही है। इस बार टीम की कोशिश फाइनल की बाधा पार कर पहली बार चैंपियन बनने की होगी।

कुलदीप को अवसर नहीं मिलने पर मनिंदर ने उठाये सवाल

चंडीगढ (ईएमएस)। गुजरे जमाने के दिग्गज स्पिनर रहे मनिंदर सिंह ने कुलदीप यादव की लगातार उपेक्षा पर सवाल उठाये हैं। मनिंदर ने कहा है कि कुलदीप को किस कारण अंतिम ग्यारह में शामिल नहीं किया जा रहा है ये समझ से परे है। मनिंदर के अनुसार कुलदीप का प्रदर्शन हमेशा ही अच्छा रहा है। इस पूर्व क्रिकेटर के अनुसार लगता है कि टीम प्रबंधन को उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा नहीं है, इसी वजह से उन्हें हर प्रारुप में काफी कम मौके मिल रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो कुलदीप ने अपने एकदिवसीय करियर में 124 मैचों में 201 विकेट लिए हैं, जो मौजूदा भारतीय टीम के किसी भी अन्य गेंदबाज से अधिक हैं। इसके बावजूद, न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टी20 सीरीज में उन्हें एक भी मैच खेलने का अवसर नहीं मिला। आम तौर पर उपमहाद्वीप के बाहर टीम संतुलन की बात कहते हुए कुलदीप को बाहर रखा जाता है। इसके तहत मुख्य कोच गौतम गंभीर नंबर 8 तक बल्लेबाजी वाली टीम को प्राथमिकता दे रहे हैं। हार्दिक के नहीं होने के कारण भारत ने आमतौर पर तीन विशेषज्ञ तेज गेंदबाजों को रखा है। इसी कार पिछले दो साल में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (सेना देश) में खेले गए 35 मुकाबलों में से कुलदीप सिर्फ तीन में ही खेल पाए हैं। मनिंदर ने कहा कि कुलदीप एकदिवसीय और टी20 के लिए सबसे अच्छे गेंदबाज हैं पर इसके बाद भी उनको जगह नहीं मिल रही है। इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में भी प्रभावी रहेंगी। उन्होंने इंग्लैंड में हुई टेस्ट सीरीज का उदाहरण दिया, जहाँ उनका मानना था कि अगर कुलदीप को अवसर मिलता हो तो भारत वह सीरीज 3-1 से जीत जाता। मनिंदर ने कुलदीप की तुलना पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर मुरली कार्तिक से भी की, जिन्हें कप्तान सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ का पूरा भरोसा नहीं मिल पाया था। मनिंदर का मानना है कि कुलदीप यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।



भारतीय महिला हॉकी टीम एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के इरादे से उतरेगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय महिला हॉकी टीम 19 नवंबर से होने वाली एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) में अपना खिताब बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगी। भारतीय टीम ने अब तक इस टूर्नामेंट में तीन जीत हासिल की है। छह देशों का ये टूर्नामेंट 19 नवंबर से भोपाल में खेला जाएगा। इसमें भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत मलेशिया के खिलाफ मैच से करेगी। भारतीय टीम ने हाल ही में एशियाई खेलों में खिताब जीता था जिससे उसके हौंसले बुलंद है। ऐसे में वह इस टूर्नामेंट में भी जीत का सिलसिला बनाये रखना चाहेगी। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा जापान, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया भाग लेंगी। यह टूर्नामेंट राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा, जिसमें शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। ऐसे में भाग ले रही सभी छह टीमें इस टूर्नामेंट में खिताब जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देंगी हालांकि भारतीय टीम को इस दौरार घरेलू मैदान पर खेलने का लाभ मिलेगा। भारतीय टीम ने इससे पहले साल 2016, 2023 और 2024 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी है। ऐसे में वह चौथी बार ये खिताब जीतना चाहेगी।भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 19 नवंबर को मलेशिया के खिलाफ करेगी।

रंग संसार



सिल्वर स्क्रीन पर कई हीरोइनों के साथ रोमांस कर चुके हैं शाहरुख खान

मुंबई (यशभारत)। अपने दशकों लंबे करियर में सुपरस्टार शाहरुख खान ने सिल्वर स्क्रीन पर कई हीरोइनों के साथ रोमांस किया है। चाहे काजोल हो या दीपिका पादुकोण, शाहरुख के साथ हर हीरोइन की जोड़ी ने सिनेमाप्रेमियों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री पर दर्शक आज तक बेशुमार प्यार लुटाते हैं। शाहरुख खान आज 61 साल के हो चुके हैं। उनके जन्मदिन के इस विशेष अवसर पर, आइए एक नजर डालते हैं शाहरुख खान की उन सात यादगार ऑनस्क्रीन जोड़ियों पर, जिन्होंने अलग-अलग दशकों में बड़े पर्दे पर प्यार की अनोखी दास्तां रची है और दर्शकों का दिल जीता है। बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसी ऑनस्क्रीन जोड़ी हो, जिसने शाहरुख और काजोल जैसा जादू बिखेरा हो। 1993 में बाजीगर से शुरू हुआ यह सफर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक पहुंचा। पर्दे पर उनका नोक-झोंक भरा अंदाज, गहरे इमोशनल सीन और सुरीले गानों ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया।

साल 2015 में आई फिल्म दिलवाले में जब दोनों दोबारा साथ आए, तो पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। शाहरुख खान और जूही चावला की जोड़ी जब भी बड़े पर्दे पर आई, एक अलग ही ताजगी और मिठास लेकर आई। यश बॉस, डुप्लीकेट और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में उनकी कमाल की कॉमिक टाइमिंग और सहज रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिली।

मैं बिकिनी पहनूंगी, किसी के बाप का क्या जा रहा है- सोनारिका

मुंबई (यशभारत)। मशहूर टीवी एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया द्वारा सालों पहले बिकिनी में अपनी तस्वीरें साझा करने पर भयंकर ट्रोलिंग का शिकार होने के बाद अब इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्रोलर्स को बेहद सख्त लहजे में जवाब दिया है। देवों के देवज्‌ महादेव में मां पार्वती का किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुईं सोनारिका ने साफ कहा है कि उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। सोनारिका ने बेबाक अंदाज में कहा, मैं बिकिनी पहनूंगी। किसी के बाप का क्या जा रहा है। यह पूरा मामला साल 2016 का है, जब सोनारिका मॉरीशस वेकेशन पर गई थीं और वहां से उन्होंने बिकिनी में कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थीं। इन तस्वीरों के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा। लोगों ने उनके लिए संस्कारहीन और बेशर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, और कई यूजर्स ने अश्लील और भद्दे कमेंट भी किए थे। एक्ट्रेस ने बताया कि जब यह ट्रोलिंग हुई, तब देवों के देवज्‌ महादेव शो खत्म हो चुका था। इसके बाद भी वह कई सीरियल में काम कर चुकी थीं, लेकिन लोग उनका इंटरव्यू सिर्फ इस सवाल के लिए लेना चाहते थे कि पार्वती का रोल करने वाली एक्ट्रेस बिकिनी कैसे पहन सकती है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में पहुंची सोनारिका ने इस पूरे विवाद पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वह आज भी बिकिनी पहनने से पीछे नहीं हटेंगी, और उन्हें यह सफाई क्यों देनी चाहिए कि उनके पति या पिता को उनके कपड़ों से कोई परेशानी नहीं है। एक्ट्रेस के अनुसार, असल बात यह है कि उन्हें खुद बिकिनी पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने इस सोच पर सवाल उठाया कि किसी शो में किरदार निभाने का मतलब यह नहीं है कि असल जिंदगी में भी इंसान को वैसा ही रहना होगा। सोनारिका ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि अगर कोई पानी में जा रहा है तो वह बिकिनी ही पहनेगा, पानी में सूट पहनकर तो नहीं जा सकती।







गाना तू मिल जाए की शूटिंग के दौरान गर्भवती थी दीपिका

मुंबई (यशभारत)। आगामी फिल्म किंग का पहला गाना तू मिल जाए रिलीज कर दिया गया है। शाहरुख खान के जन्मदिन के अवसर पर जारी किये गए इस गाने में शाहरुख और दीपिका पादुकोण की रोमांटिक केमिस्ट्री दर्शकों का दिल जीत रही है। दोनों विदेशी लोकेशन पर एक-दूसरे की बाहों में बाहें डाले डांस करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस गाने की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पाँच महीने की गर्भवती थीं। साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्मों पठान और जवान में शाहरुख और दीपिका की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। अब तीन साल बाद यह सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है। किंग फिल्म के पहले गाने तू मिल जाए में दीपिका और शाहरुख का रोमांटिक अंदाज इस फेस्टिव सीजन को और खास बना रहा है। दीपिका ने गाने में कई अलग-अलग लुक अपनाए हैं, और उनके हर अंदाज़ को सराहना मिल रही है। यह जानकर सभी हैरान हैं कि इस गाने की शूटिंग के दौरान दीपिका अपनी दूसरी बेटी देवी के साथ पाँच महीने की गर्भवती थीं। दीपिका ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की खबर दुनिया के सामने आने के कुछ समय बाद ही शाहरुख के साथ गाने की शूटिंग के लिए केपटाउन का रुख किया था। अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान भी उन्होंने पूरी लगन और व्यावसायिकता के साथ गाने की शूटिंग जारी रखी। उन्होंने अपने काम के प्रति समर्पण का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया.

रामायण की वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 75 करोड़ के पार

मुंबई (यशभारत)। अपकमिंग फिल्म रामायण ने अपनी रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाना शुरू कर दिया है। नितेश तिवारी निर्देशित इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की वर्ल्डवाइड एडवांस बुकिंग का आंकड़ा 75 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है। भारत में भी फिल्म के टिकटों की धड़ाधड़ बिक्री हो रही है, और यह 5 नवंबर को बड़े पर्दे पर आने से पहले ही हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। रामायण की रिलीज डेट जैसे-जैसे करीब आ रही है, वैसे-वैसे इसकी एडवांस बुकिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। भारत में टिकट बिक्री में भारी उछाल आया है, और विदेश में भी फिल्म लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। दशहरे पर वर्ल्डवाइड रिलीज के लिए रामायण की एडवांस बुकिंग 15 दिन पहले ही शुरू कर दी गई थी। शुरुआती दस दिनों तक मुख्य रूप से हिंदी वर्जन के शो ही उपलब्ध थे, लेकिन अब पूरे देश में नए सिनेमाघरों में प्री-सेल्स तेजी से शुरू हो गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, सोमवार सुबह तक फिल्म के लिए स्क्रीन्स की संख्या बढ़कर



3,500 हो गई है, जिसमें से पिछले दो दिनों में ही 1,000 स्क्रीन्स जोड़ी गई हैं। रिलीज से तीन दिन पहले तक रामायण ने भारत में एडवांस बुकिंग से 37 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है। इसमें से पहले दिन के लिए 22 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जबकि बाकी रकम एक्सटेंडेड वीकेंड में बंटी हुई है। पूरे भारत में रामायण के अब तक करीब 9 लाख टिकट एडवांस में बिक चुके हैं। हिंदी बेल्ट में फिल्म की मांग सबसे ज्यादा है, जबकि कन्नड़ और तेलुगु वर्जन्स ने भी क्रमशः 4 करोड़ और 2 करोड़ से अधिक के टिकट बेचे हैं। विदेशों में भी रामायण को लेकर जबरदस्त माहौल है। उत्तरी अमेरिका में फिल्म की रिलीज से एक दिन पहले, 4 नवंबर को पेड प्रिव्यू रखे गए हैं। सोमवार सुबह तक फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से एडवांस बुकिंग में 3.9 मिलियन डॉलर (लगभग 32 करोड़) की कमाई कर ली है, जिसमें अकेले अमेरिका के पेड प्रिव्यू से आया 1.5 मिलियन से अधिक का कलेक्शन शामिल है। नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनी यह फिल्म दो पार्ट में लाई जा रही है। इसका पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगा।

डीएमएफ की कार्ययोजना में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना को दें प्राथमिकता - राज्यपाल

'खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए दो वर्ष का रोडमैप तैयार करने के दिए निर्देश, बस्तर में विकास कार्यों पर विशेष जोर'

यश भारत

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा है कि जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास और वहां के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जाना चाहिए। इसके तहत पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए सुनियोजित कार्ययोजना तैयार करने के साथ पर्यावरणविदों का भी सहयोग लिया जाए।

राज्यपाल डेका आज लोक भवन में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) की गतिविधियों, खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों तथा आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने डीएमएफ की राशि के प्रभावी और सुनियोजित उपयोग के लिए कम से कम दो वर्ष का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने



कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए डीएमएफ से आवश्यक कार्य किए जाएं। साथ ही उद्योगों से चर्चा कर पर्यावरणीय मानकों और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को अभियान के रूप में संचालित करने पर उन्होंने जोर दिया। राज्यपाल ने नदियों से रेत उत्खनन के संबंध में वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि रेत रहेगी तो पानी रहेगा और पानी रहेगा तो रेत रहेगी। रेत खदानों में वैज्ञानिक तरीके से उत्खनन को लेकर विशेष अभियान चलाने की बात भी कही।

राज्यपाल ने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे आम जनता से संवाद करें और उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को समझें। इसके अनुरूप डीएमएफ की कार्ययोजना तैयार की जाए। विकास कार्यों के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लेना आवश्यक है। प्रशासन को जनता के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए और उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कौन से कार्य किए जा सकते हैं तथा किन कार्यों को करना संभव नहीं है। उन्होंने डीएमएफ की नियमित बैठकें आयोजित करने को कहा, ताकि कार्यों की प्रगति की समीक्षा और आवश्यक निर्णय समय पर लिए जा सकें।

राज्यपाल ने कहा कि डीएमएफ के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण और विकास से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विशेष उद्देश्यों के लिए डीएमएफ के अंतर्गत कार्य निर्धारित किए जाते हैं, उन कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाना चाहिए।

राज्यपाल ने बस्तर क्षेत्र में डीएमएफ के माध्यम से विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग मुख्यधारा में लौट आए हैं, उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उनके पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे विकास की प्रक्रिया से जुड़ सकें।

लोकतंत्र को कमजोर करने और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ भाजपा ने निकाली लोकतंत्र बचाओ - अराजकता हटाओ पदयात्रा

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र की जननी है हमारा देश : सीएम साय

यश भारत

रायपुर। भाजपा रायपुर जिला द्वारा आज राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में आयोजित लोकतंत्र बचाओ - अराजकता हटाओ पदयात्रा एवं विशाल रैली 10,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। रैली विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम के विरोध में निकाली गई, जिसमें रायपुर शहर की जनता आक्रोशित नजर आई और विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। विपक्ष द्वारा लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम पूरी तरह झूठा और जनता को गुमराह करने वाला है। जनता अब विपक्ष के इस भ्रमजाल में आने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है और संविधान की रक्षा के लिए भाजपा पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन के लोग सरकार में बैठने और प्रधानमंत्री बनने की लालसा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का विरोध करते-करते अब पूरे देश का विरोध करने पर उतारू हो गए हैं और देश में अराजकता फैलाकर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे



हैं, लेकिन भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जननी है, दुनिया के सभी देश हमारे लोकतंत्र की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये चुनाव हार जाते हैं तो कभी ईवीएम में दोष लगाते हैं, कभी चुनाव आयोग में दोष लगाते हैं। जब जीत जाते हैं तो वही चुनाव आयोग उन्हें अच्छा लगने लगता है। कांग्रेस का यही दोहरा चरित्र उसकी हताशा को दर्शाता है। साय ने कहा कि कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन के लोग भाजपा-एनडीए के ऊपर वोट चोरी और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हैं, जबकि खुद कांग्रेस का इतिहास ही लोकतंत्र की हत्या का इतिहास है। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब देश आजाद हुआ और प्रधानमंत्री चुनने की बात आई, उस समय कांग्रेस के 12 नेता सरदार वल्लभभाई पटेल जी के पक्ष में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पक्ष में एक भी नेता नहीं था। इसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो असली वोट चोर कौन हुआ? वोट चोर कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में और हर जिला-जिला में लोकतंत्र बचाओ - अराजकता हटाओ पदयात्रा का आयोजन हो रहा है, ताकि जनता के सामने कांग्रेस की अराजक मानसिकता का सच लाया जा सके।

148 करोड़ जनता लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए सजग खड़ी है - देव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि आज रायपुर की इस पावन भूमि पर लोकतंत्र बचाओ - अराजकता हटाओ पदयात्रा का आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा का महाअभियान है। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक दल अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। आजादी के बाद जिस दल का पूरे देश में शासन हुआ करता था, आज वह गिने-चुने तीन-चार राज्यों में ही सिमट कर रह गया है। जनविरोधी नीतियां और देशविरोधी सोच आज उस दल का आवश्यक अंग बन चुकी हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र की जड़ें अत्यंत मजबूत हैं, यहां 148 करोड़ जनता लोकतंत्र, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए सजग खड़ी है।

गन्ना किसानों को अब 425 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा खरीदी मूल्य, बोनस से भी बढ़ेगी आय

■ कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने केरता शक्कर कारखाने में किसानों को वितरित की बोनस राशि, जैविक खेती और फसल विविधीकरण अपनाने पर दिया जोर

यश भारत



रायपुर। छत्तीसगढ़ में गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने गन्ने का खरीदी मूल्य बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके साथ ही किसानों को बोनस का लाभ भी दिया जा रहा है। सूरजपुर जिले के माँ महामाया शक्कर कारखाना केरता में गुरुवार को आयोजित आभार एवं कृषक चौपाल कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किसानों को बोनस राशि वितरित की। गन्ना खरीदी मूल्य में वृद्धि के निर्णय पर किसानों ने राज्य सरकार के प्रति आभार जताया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के मजबूत आधार हैं। उनके परिश्रम से ही देश की खाद्यान्न जरूरतें पूरी होती हैं। किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की प्रगति का आधार है।

मंत्री ने कहा कि सरगुजा अंचल के गन्ना उत्पादक किसानों की जरूरतों और मांग को देखते हुए माँ महामाया शक्कर कारखाने की स्थापना की पहल की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ क्षेत्र में कृषि आधारित औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था। अब कारखाने को और विकसित करने तथा वैल्यू एडिशन के माध्यम से इसकी आर्थिक संभावनाएं बढ़ाने की जरूरत है।कृषि मंत्री ने किसानों से धान के साथ दलहन और तिलहन जैसी वैकल्पिक फसलों को भी अपनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि धान के स्थान पर इन वैकल्पिक फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत किसानों को 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण से खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है।

नेताम ने आधुनिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर जोर देते हुए कहा कि वैज्ञानिक तकनीक और कृषि विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से कम पानी तथा संतुलित उर्वरक के उपयोग में भी बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का उल्लेख करते हुए किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया।

प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते ने गन्ना खरीदी मूल्य में वृद्धि के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि माँ महामाया शक्कर कारखाने की स्थापना से लेकर इसके विकास तक किसानों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के प्रयासों से गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।

कलेक्टर रेना जमील ने कहा कि रिवॉल्विंग फंड की घोषणा से गन्ना उत्पादक किसानों में नया उत्साह है। आगामी कार्ययोजना के तहत कारखाने की रिकवरी दर बढ़ाने और गन्ने की खेती का रकबा विस्तार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इससे कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ किसानों को भी अधिक आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

प्रमुख विकास कार्यों को गति दें: विकासशील

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य में प्रस्तावित विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा भविष्य की योजनाओं को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि प्रस्तावित निर्माण कार्यों के लागत तुलनात्मक विश्लेषण में पूरी स्पष्टता रखी जाए, जिससे प्रत्येक परियोजना की लागत का उचित और यथार्थवादी आकलन संभव हो सके। उन्होंने आगामी बजट में शामिल किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की समय रहते पहचान करने और उनकी आवश्यक प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियां पहले से ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की प्रगति से अवगत कराया।



मुख्य रूप से इन परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कांकेर जिला में भानुप्रतापपुर-कांकेर-पंखाजूर मार्ग पर पुल-पुलिया सहित सड़क निर्माण कार्य। बिलासपुर क्षेत्र में बिलासपुर-कटनी रेल मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण तथा बिलासपुर जिले में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण का कार्य शामिल है। दुर्ग एवं अन्य परिक्षेत्र में नगरी-कांकेर-भानुप्रतापपुर-मानपुर-राजनांदगांव-कवर्धा-फास्टरपुर कुंडा मार्गों तथा कुम्हारी, अहिवारा-धमधा-गंडई-साल्हेवारा मार्गों का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य।

एक बार फिर राज्य का जल, जंगल, जमीन अडानी को सौंपा जा रहा – दीपक बैज

यश भारत

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सूरजपुर जिले में अडानी के द्वारा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर लगाया जा रहा है। यह पावर प्लांट 4800 मेगावाट का है तथा कोयला आधारित पावर प्लांट है। इसमें बड़ी संख्या में वन भूमि भी प्रभावित हो रही है। इसके भूमि के पूरी जानकारी के बिना डबल इंजन की सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति देने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कंपनी के पास अभी केवल 465.92 हेक्टेयर भूमि है जबकि प्रोजेक्ट में इन्होंने 673.5 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता बताई है। इतनी भूमि वहां है ही नहीं शेष 207.58 हेक्टेयर भूमि वन भूमि है, जिसके लिए कंपनी वनभूमि को डायवर्सन के लिए आवेदन तक नहीं किया है लेकिन इस वन भूमि के पर्यावरण स्वीकृति का आवेदन ले लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि यह प्रोजेक्ट



गुम्गा, चिरवान और मुड़गांव जैसे संरक्षित वनों तथा सलका, नारायणपुर जैसे गांवों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक बगल में (150 मीटर से 250 मीटर की दूरी पर) स्थित है। वन भूमि पर ही पावर प्लांट क्यों लगाया जा रहा है?प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 84 मिलियन घन मीटर पानी प्रतिवर्ष लगेगा, यह पानी कहां से आयेगा? इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। यहां पानी भी हसदेव बांगो जलाशय से ही मिलना संभव होगा। बांगो इस क्षेत्र सिंचाई का प्रमुख जलाशय से है। यहां से यदि अडानी को पानी दिया जाएगा तो किसानों का क्या होगा? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वन भूमि पर पावर प्लांट लगाये जाने तथा इसकी पर्यावरण स्वीकृति देने की कोशिश और बांगो जलाशय से पानी दिये जाने का कांग्रेस विरोध करती है। भूमि का कोई क्लीयर नहीं वन भूमि का, बिना ग्राम सभा की सहमति से देने का प्रस्ताव, वन भूमि का डायवर्सन का कोई आवेदन नहीं।

धनतेरस से भाई दूज तक, 6 से 11 तक रहेगी त्योहारों की धूम

रायपुर। इस साल 2026 में पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत 6 नवंबर को धनतेरस के साथ होगी। इस वर्ष नरक चतुर्दशी और बड़ी दिवाली का त्योहार 8 नवंबर को मनाया जाएगा। इसके बाद 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी और 11 नवंबर को भाई दूज के साथ इस महापर्व का समापन होगा। दिवाली हिंदू धर्म के सबसे बड़े और प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने दीप जलाए थे। तभी से दिवाली मनाने की परंपरा चली आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी दिवाली का त्यौहार पांच दिन रीति रिवाज से मनाने की परम्परा चली आ रही है। दिवाली के त्योहारों की शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज के साथ इनका समापन होता है। इस दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं।



छत्तीसगढ़ राज्योत्सव-2026 में डॉ. बहुरन पटेल को मिला संस्कृत भाषा सम्मान

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयासों से हुआ। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में राज्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक किया गया। इस अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 36 विभूतियों और संस्थाओं को राज्य अलंकरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। संस्कृत को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से संस्कृत के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय योगदान देने वाले विभूतियां को प्रतिवर्ष संस्कृत भाषा सम्मान से अलंकृत किया जाता है। संस्कृत भारती महानगर रायपुर के अध्यक्ष डॉ. लूनेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस वर्ष राज्योत्सव में संस्कृत



महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक व्याकरणाचार्य डॉ. बहुरन सिंह पटेल को संस्कृत भाषा सम्मान से अलंकृत किया गया है। ज्ञात हो कि पटेल जी महाविद्यालय में अध्यापन के साथ-साथ संस्कृत भारती नामक संस्था से जुड़कर संस्कृत के प्रचार-प्रसार में विशेष योगदान देते हैं। राज्योत्सव के समारोप कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 के समापन समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले विभूतियों एवं संस्थाओं को प्रतिष्ठित राज्य अलंकरण पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस समारोह में साहित्य, कला, संस्कृति, पत्रकारिता, खेल, कृषि, समाजसेवा, जनजातीय उत्थान, महिला सशक्तिकरण, सहकारिता, श्रम, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया।

रायपुर सहित छह जिलों की बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिये 286 करोड़ की नई पारेषण लाइन ऊर्जीकृत

प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला द्वारा 400 केवी धरदेही-बिलासपुर पुल पारेषण लाइन का ऊर्जीकरण

रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा तथा भाटापारा-बलौदाबाजार होंगे लाभान्वित

यश भारत

रायपुर। रायपुर सहित छह जिलों की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 286 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 400 केवी डीसीडीएस क्वाड मूस धरदेही-बिलासपुर पूल (पावरग्रिड-पीजीसीआईएल) पारेषण लाइन को आज दोपहर 12:34 बजे सफलतापूर्वक ऊर्जीकृत किया गया। लगभग 50.7 किलोमीटर लंबी इस पारेषण लाइन के चालू होने से रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा तथा भाटापारा-बलौदाबाजार जिलों की विद्युत पारेषण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे अधिक एमवीए विद्युत शक्ति का पारेषण संभव होगा और वर्तमान एवं भविष्य की विद्युत मांग पूरी करने में सहायता मिलेगी।छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला की उपस्थिति में पारेषण लाइन का ऊर्जीकरण संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (लाइन) संजय पटेल, कार्यपालक निदेशक (सबस्टेशन), बिलासपुर श्रीमती कल्पना घाटे तथा कार्यपालक निदेशक, बिलासपुर क्षेत्र, सीएसपीडीसीएल ए.के. अम्बस्थ सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस 400 केवी डीसीडीएस क्वाड मूस पारेषण लाइन के निर्माण के दौरान चार स्थानों पर अन्य विद्युत लाइनों की क्रॉसिंग का कार्य हॉटलाइन पद्धति से सफलतापूर्वक किया गया। इसके अतिरिक्त रेलवे क्रॉसिंग का कार्य भी बिना पावर ब्लॉक लिए हॉटलाइन स्ट्रिंगिंग पद्धति से पूरा किया गया। परियोजना निर्माण के दौरान राइट ऑफ वे (मार्गाधिकार) से संबंधित कई गंभीर चुनौतियां भी सामने आईं। इन चुनौतियों के बावजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बेहतर समन्वय, तकनीकी दक्षता और टीमवर्क से परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर चालू किया गया। नई पारेषण लाइन से अधिक विद्युत शक्ति का पारेषण संभव होगा। इससे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की वर्तमान एवं भविष्य की विद्युत मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।



स्वामी प्रकाशक मुद्रक आशीष कुमार शुक्ला , मिशन मीडिया (प्रा.लि.) प्लाट नम्बर -9/1 छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्प्लेक्स,रजबंधा मैदान, रायपुर छत्तीसगढ़ -492001 से मुद्रित एवं हॉउस नम्बर 18/303 सेक्टर 27 ,नवा रायपुर ,रायपुर छत्तीसगढ़ -492018 से प्रकाशित। संपादक आशीष कुमाार शुक्लाा सलाहकार संपादक श्याम कटारे
प्रबंध संपादक अजय क्षत्रे, स्थानीय संपादक अरविंद कुमाार पांडेय मो .-9827117441 RNI-CTHI/26/A5 206 ईमेल -raipuryashbharat@gmail.com (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) , सिटी ऑफिस- आर्ययन टॉवर द्वितीय तल द्रोणाचार्य स्कूल के पास रायपुर, मो .-9111201000 (न्यायालय क्षेत्र अधिकार रायपुर)